

विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम के दिशा निर्देश से हजारों वाहन मालिक परेशान

संज्ञक बाटला

नई दिल्ली। सरकारी छुट्टी के दिन पर भी लोगों को जारी करवा दी वाहन जांच की तारीख और फिर विभाग से करवा दिए बुधवार शाम को सभी को संदेश "अगले वकिंग डे पर अपने वाहनों की जांच करवाने पहुंचें"

वाहन जांच शाखा की वाहनों को जांचने की अंतिम क्षमता 300 वाहन और वह पहले से फूल फिर वीरवार के 300 वाहनों की जांच कैसे होगी जिन्हें शहजाद आलम के दिशा निर्देश से संदेश पहुंचा।

जब वीरवार को समय प्राप्त वाहन आज सुबह ही झूलझुली जांच शाखा पर पहुंचे तो शाखा के अधिकारियों ने अपनी असमर्थता जाहिर की सच्चाई के साथ

क्या विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम आईएसएम को इसकी जानकारी नहीं थी जो उनके द्वारा परेशान वाहन मालिकों को और परेशान किया वहां भिजवाकर शहजाद आलम द्वारा ही कुछ दिनों पहले क्षमता से कई गुणा वाहनों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती बुराई वाहन जांच शाखा से झूलझुली वाहन जांच शाखा पर हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए थे (सिर्फ एक प्राइवेट कम्पनी को



जिसका टैडर खत्म हुए काफी समय हो चुका है पर इसी अधिकारी द्वारा बार बार एक्टेशन के बल पर चल रहा है फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए)

आज झूलझुली शाखा के बाहर दो गुप में काफी झगड़ा हुआ, ऐसे में क्या करें वाहन मालिक और चालक।

मोटर वाहन नियम के तहत बिना वाहन जांच पत्र के वाहन चलाना जुर्म है और अब दिल्ली में वाहन की जांच करवाने का अर्थ है जान हथेली पर रख

कर जाना। कौन समझेगा दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों के दिल का हाल। इस अधिकारी के आदेश से उनके लिए तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई

परिवहन मंत्री भी चुप रहेंगे क्योंकि यह झूलझुली जांच शाखा उनके अपने क्षेत्र में स्थित है जहां से वह स्वयं एमएएच है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिक

और चालक कल दोपहर को इस बाबत पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं।

अब जानना यह जरूरी है की वीरवार को वाहन जांच का समय प्राप्त वाहन मालिक क्या करें क्योंकि एक दिन वाहन जांच देरी होने के साथ ही सरकार और परिवहन विभाग वाहन मालिक से 1050 रुपए जुर्माने और उसके पश्चात 50 रुपए प्रति दिन का जुर्माना वसूल

करने के बाद ही वाहन जांच की आज्ञा प्रदान करते हैं। आखिर एक अधिकारी के कारण 300 वाहनों के मालिक और चालक परेशान हो रहे हैं ऊपर से जुर्माना अलग, बताए कहा का इसाफ है यह ?

सबसे बड़ी बात यह है की फिर भी ना तो आयुक्त परिवहन, ना ही मंत्री परिवहन, ना हो मुख्य सचिव दिल्ली और ना ही उपराज्यपाल दिल्ली ने इस अधिकारी से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा।

टैम्पल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)



रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण का असर मेट्रो के परिचालन पर, डीएमआरसी ने दिया अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए अपने फेरों की संख्या बढ़ाने जा रही है। ग्रेप दो के प्रतिबंध लागू होने पर मेट्रो प्रतिदिन 40 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी और ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू होने पर 20 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाएंगे। त्योहारों के समय सड़कों पर बढ़ने वाले दबाव को कम करने के लिए भी यह कदम उठाया जा रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने पर मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे, ताकि लोग आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन के रूप में मेट्रो का अधिक इस्तेमाल कर सकें। साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने त्योहारी सीजन में सड़कों पर जाम से बचने और प्रदूषण को रोकथाम के लिए लोगों से निजी वाहन छोड़कर आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो प्रतिदिन करीब 4200 फेरे लगाती है। ग्रेप दो के प्रतिबंध लागू होने पर मेट्रो प्रतिदिन 40 फेरे अतिरिक्त



लगाएगी। एयर इंडेक्स 300 से अधिक बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेप दो के प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। ऐसे में मेट्रो सभी कार्यदिवस के दिन 40 फेरे अतिरिक्त लगाएगी। इसके अलावा ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू होने पर 20 फेरे अतिरिक्त बढ़ाए जाएंगे। तब सामान्य दिनों के मुकाबले प्रत्येक कार्यदिवस के दिन 60 फेरे अतिरिक्त बढ़ जाएंगी।

त्योहारों के समय सड़कों पर बढ़ता है

दबाव डीएमआरसी का कहना है कि त्योहार के समय सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इस वजह से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की भी समस्या होती है। इससे बचने के लिए लोग मेट्रो में अधिक सफर कर सकते हैं। मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है, इसलिए मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

हाफ मैराथन के चलते परिचालन होगा

जल्दी

दिल्ली हाफ मैराथन के कारण रविवार को दिल्ली मेट्रो का परिचालन तड़के 3 बजकर 15 मिनट से शुरू होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और ग्रे लाइन को छोड़कर अन्य सभी कॉरिडोर पर मेट्रो इसी समय पर उपलब्ध रहेगी। मैराथन में भाग लेनेवालों के लिए विशेष क्यूआर कोड वाले कलाई बैंड होंगे और वे निःशुल्क मेट्रो में सफर कर सकेंगे। वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी हाफ मैराथन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक हाफ मैराथन के मद्देनजर रविवार को सुबह 11 बजे तक दक्षिण और मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली हाफ मैराथन में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसे सुबह 4.45 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी इंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में धावकों के पहुंचने की संभावना है।

अब अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू करेगा डीटीसी पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगलुरु, कोटा जैसे शहरों तक जाएगी

हाल में डीटीसी की बोर्ड बैठक में डीटीसी ने एनसीआर में प्रीमियम बसें चलाने और इंटरसिटी संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी को अन्य राज्यों में बस सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत अब पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगलुरु, कोटा जैसे शहरों में बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों को राजस्व-साझाकरण मॉडल पर चलाया जाएगा।

हाल में डीटीसी की बोर्ड बैठक में डीटीसी ने एनसीआर में प्रीमियम बसें चलाने और इंटरसिटी संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन बसों का संचालन शुरू हो सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी को अन्य राज्यों में

बस सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि बसों में एनसीआर के शहरों, पड़ोसी राज्यों और दूरदराज के स्थानों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें और एप आधारित टिकटिंग होगी। इसके साथ ही पुश-बैक सीटें और अन्य सुविधाएं होंगी। 200 किलोमीटर तक की सेवाओं के लिए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इससे अधिक की दूरी तक चलने वाली बसें वीएच 6 बसें चलेगीं। बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिंग बटन लगे होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन बस सेवा का उद्देश्य यह है कि लोगों को निजी कारों का उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना।

डीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि एनसीआर और लंबी दूरी तक जाने वाली प्रीमियम बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। वाईफाई, जीपीएस आदि सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी।

2001 तक अंतरराज्यीय बस सेवा की गई थी बंद डीटीसी 2001 तक हिमाचल

प्रदेश, पंजाब, यूपी और राजस्थान में नियमित बसों का संचालन करता था, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी की बसों का बेड़ा सीएनजी पर कर दिया गया। ऐसे में लंबी दूरी तक यात्रा नहीं हो सकती थी। 2010 तक, डीटीसी का अंतरराज्यीय परिचालन एनसीआर तक सीमित हो गया। औसतन एक सीएनजी से चलने वाली बस की रेंज एक बार भरने पर लगभग 250 किमी होती है। सेवाओं को सीमा के भीतर के क्षेत्रों जैसे मेरठ या हावड़ा तक विस्तारित करने की योजना थी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई।

बस अट्टे के लिए मुकरबा चौक के पास जमीन की तलाश शुरू

दिल्ली के भीतर अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही कम करने के लिए दिल्ली की सीमा पर बस अट्टा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मुकरबा चौक के पास बस अट्टा बनाने के लिए जमीन का सर्वे और ड्रॉन से जमीन को चिह्नित कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है।

दिल्ली में AQI 300 के करीब, 15 इलाके रेड जोन में; जल्द लागू होगी GRAP-2 की पाबंदियां

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब यह बहुत खराब श्रेणी की दहलीज तक पहुंच गया है। दिल्ली के 15 इलाके पहले ही रेड जोन में पहुंच चुके हैं। जानिए दिल्ली-NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का लेटेस्ट अपडेट और ग्रेडेड रिसांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण में लगने वाली पाबंदियों के बारे में।

नई दिल्ली। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और स्थानीय कारकों के कारण निरंतर बढ़ रहा प्रदूषण अब 'बहुत खराब' श्रेणी की दहलीज तक जा पहुंचा है। दिल्ली के 15 इलाके पहले ही रेड जोन में पहुंच चुके हैं। एनसीआर के शहरों का भी यही हाल है।

लिहाजा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिसांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के दूसरे चरण की पाबंदियां भी जल्द ही लागू हो सकती हैं। दिल्ली का समग्र एक्व्यूआई 300 पार होते ही यह पाबंदियां लागू जाएंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार अगले तीन दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के आसार भी नहीं हैं।

दिल्ली का एक्व्यूआई 292 रिकॉर्ड किया गया

सीपीसीबी द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार शुरुवार को दिल्ली का एक्व्यूआई 292 रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह 285 रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें सात अंकों का



इजाफा हो गया। दिल्ली के विभिन्न 15 इलाकों का एक्व्यूआई बहुत खराब श्रेणी में रहा। बुधवार को आनंद विहार का एक्व्यूआई 439, बृहस्पतिवार को 419 यानी गंधी श्रेणी में जबकि शुरुवार को 353 अर्थात बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में अभी भी वाहनों, फैक्ट्रियों का धुआं, धूल प्रदूषण जैसे स्थानीय कारण ही अधिक जिम्मेदार बने हुए हैं। हालांकि पंजाब व हरियाणा में जलाई

जा रही पराली का धुआं भी दिल्ली में प्रदूषण के लिए काफी जिम्मेदार होता है, लेकिन इस साल अभी तक दिल्ली के प्रदूषण में इस धुएं की भागीदारी बहुत अधिक नहीं हुई है। शुरुवार को एनसीआर के शहरों का एक्व्यूआई शहर एक्व्यूआई दिल्ली 292 गुरुग्राम 204

ग्रेटर नोएडा 264 गाजियाबाद 258 फरीदाबाद 242 नोएडा 242 दिल्ली के इन इलाकों का एक्व्यूआई रहा सर्वाधिक स्थान एक्व्यूआई अलीपुर 310 आनंद विहार 353

बवाना 369 बुराड़ी क्रांसींग 313 डीटीयू 317 द्वारका सेक्टर आठ 337 जहांगीपुरी 367 मुंडका 329 ओखला फेज दो 302 पटपटगंज 329 रोहिणी 355

विवेक विहार 305 वजीरपुर 380 रोहिणी 355

आज और कल बढ़ सकता प्रदूषण का स्तर

पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को प्रदूषण का स्तर खराब रहेगा। लेकिन रविवार को प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। अगले छह दिनों तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से खराब रह सकता है। मौसम इस समय बिगड़ रहा है और प्रदूषक तत्वों को बहाने में सहायक नहीं कर रहा है। ऐसे में पराली और कूड़े में आग की घटनाएं भी स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकती हैं। शनिवार को हवा की रफ्तार छह से 10 किमी प्रति घंटे और रविवार को छह से आठ किमी प्रति घंटे तक रह सकती है।

ग्रेप के दूसरे चरण में लगेगी यह पाबंदियां निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए बढ़ाई जाएगी पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवा।

आरडब्ल्यूए अपने सिक्योरिटी गार्ड को दंगी हीटर ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। डीजल जेनरेटर पर रोक रहेगी, नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे।

800 केवी से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।

क्यों भारतीय महिलाएं समर्थन की हकदार हैं, फैसले की नहीं?

विजय गर्ग



हमें महिलाओं से लगाई गई अवास्तविक अपेक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू करना चाहिए और एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जो साझा जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बढ़ावा दे। भारतीय महिलाएं प्रति सप्ताह 55 घंटे से अधिक का दायित्व निभा रही हैं। वे अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के साथ-साथ घर का प्रबंधन भी करते हैं - जिसे कोई दूसरी नौकरी भी कह सकती है। यह महिलाओं पर उनकी क्षमताओं से ऊपर प्रदर्शन करने के डराने वाले दबाव के बारे में एक परेशान करने वाले तथ्य को उजागर करता है। हालांकि नौकरी और निजी जीवन के बीच की यह समस्या दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करती है, सांस्कृतिक अपेक्षाओं, सामाजिक मानकों और लंबे समय से चली आ रही धारणा कि उन्हें यह सब करना ही होगा के कारण भारतीय महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से कठिन है।

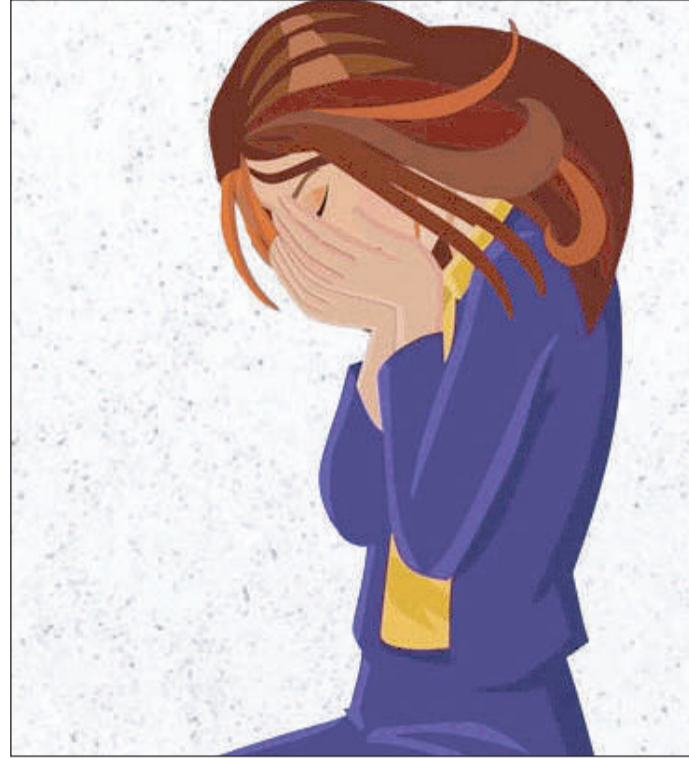
सवाल यह उठता है कि भारतीय महिलाओं पर खुद को टूटने की हद से आगे बढ़ने का इतना दबाव क्यों है? इसका उत्तर गहराई तक व्याप्त लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं में निहित है। हालांकि महिला सशक्तिकरण में प्रगति हुई है, लेकिन घर संभालने और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी

काफ़ी हद तक उनके कंधों पर है, भले ही वे अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हों।

जैसे-जैसे अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं और पेशेवर लक्ष्य हासिल कर रही हैं, पारंपरिक भूमिकाएँ निभाते रहने की उम्मीद कम नहीं हुई है। इसके बजाय, इसका विस्तार हुआ है, जिससे एक अस्थिर बाजीगरी का निर्माण हुआ है।

क्या महिलाओं को हल्के में लिया जाता है? कई मायनों में, हाँ। यह अवधारणा कि महिलाओं का जन्म इस कार्य को संतुलित करने के लिए हुआ है, इस विश्वास में प्रकट होती है कि वे प्राथमिक देखभालकर्ता, गृहिणी और विस्तारित परिवार के बाकी सदस्यों के लिए समर्थन के साथ-साथ उच्च मांग वाले पेशे को आसानी से संभाल सकती हैं। हालांकि, ऐसी धारणा उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करती है। प्रत्येक महिला की इच्छा सामाजिक रूप से थोपी गई रसुपरवुमनर छवि से प्रभावित होती है, जो उन पर अनुचित दबाव डालती है। और जब वे लड़खड़ाते हैं, तो उनका गलत मूल्यांकन किया जाता है।

लेकिन असंभव को प्रबंधित करने की कोशिश के लिए समाज को महिलाओं का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? महिलाओं से की जाने वाली उम्मीदें अक्सर उनके द्वारा किए गए बलिदानों के लिए बहुत कम



मान्यता या सराहना के साथ आती है। इसके बजाय, जब महिलाएं संघर्ष करती हैं या अपने जीवन के एक पहलू को दूसरे पर प्राथमिकता देना चुनती हैं, तो उन्हें करुणा के बजाय आलोचना का सामना करना पड़ता है।

यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से

सच है जिनके पास एक मजबूत सहायता प्रणाली का अभाव है। यदि किसी महिला के परिवार में कोई सदस्य बच्चे के पालन-पोषण या घरेलू प्रबंधन का भार साझा करने को तैयार नहीं है, तो उसे और भी अधिक भारी बोझ उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या इसके लिए उसे दोषी ठहराया

जाना चाहिए? कदापि नहीं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई भारतीय महिलाएं शिक्षक भी हैं, एक-एक पेशा जिसमें भावी पीढ़ियों को भलाई के लिए पोषण, धैर्य और निरंतर समर्पण की आवश्यकता होती है।

ये महिलाएं कक्षा में युवा दिमाग को आकार दे रही हैं और साथ ही घर पर अपने परिवार की देखभाल भी कर रही हैं। समाज कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि बिना किसी निर्णय के उन्हें वह स्थान और स्वतंत्रता दे जिसके वे हकदार हैं।

अब समय आ गया है कि हम, एक समाज के रूप में, यह पहचानें कि महिलाओं का मूल्य उनकी रयह सब करने की क्षमता से नहीं मापा जाता है। हमें उनसे लगाई गई अवास्तविक अपेक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू करना चाहिए और इसके बजाय, एक ऐसी संस्कृति की वकालत करनी चाहिए जो साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा दे। महिलाओं को उनके प्रयासों में सहायता करना - चाहे उनके करियर में हो या घर पर - उन्हें निर्णय के बिना विकल्प चुनने की आजादी देकर आवश्यक है। तभी हम उन अनावश्यक दबावों को कम करना शुरू कर सकते हैं जो लंबे समय से भारतीय महिलाओं के कंधों पर बोझ बने हुए हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

पर्यावरण पाठशाला - चींटियों को सही स्थान पर खिलाना - एक नैतिक शिक्षा

अंकुर

हमारे पुराणों और पूर्वजों ने हमेशा जीवों की सेवा को पुण्य कार्य माना है। चींटियों को आटा, चीनी या गुड़ खिलाना हमारे शास्त्रों में एक शुभ कार्य के रूप में माना जाता है, जिससे अच्छा कर्म और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन आज के समय में, हमें इस परंपरा को सही तरीके से अपनाने की जरूरत है ताकि हम अनजाने में बुरे कर्म न करें।

सांस्कृतिक स्थानों पर चींटियों को खाना खिलाने का विचार अच्छा है, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि कहाँ और कैसे खिलाना है। यदि हम रास्तों या पगडंडियों पर खाना डालते हैं, तो चींटियों की जान जोखिम में आ जाती है। वहाँ से गुजरने वाले लोग, दौड़ने वाले, या साइकिल चलाने वाले अनजाने में उन पर पैर रख सकते हैं और चींटियों की मौत का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार, एक ओर हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर अनजाने में बुरा कर्म भी कर बैठते हैं।

चींटियों को सही स्थान पर खिलाना - एक नैतिक शिक्षा

यदि आप चींटियों को खाना खिलाना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप उन्हें ऐसी जगह पर खिलाएँ जो सांस्कृतिक मार्ग या पगडंडी से दूर हो, जैसे किसी बगीचे के किनारे। इस तरह से, चींटियों को नुकसान नहीं होगा, और आप बिना किसी बुरे कर्म के अपना अच्छा कार्य कर पाएँगे। यह एक गंभीर मुद्दा है और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना और सही दिशा में कदम



पर्यावरण पाठशाला

उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम प्रकृति के हर जीव के प्रति संवेदनशील होंगे, तो हमारा समाज और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे।

आइए, एक ग्रीन बडी बनें और चींटियों को भोजन खिलाने का छोटे-छोटे बातों का ध्यान रखें। नैतिक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएँ और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। इस तरह हम पर्यावरण और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व निभा सकेंगे।

सांस्कृतिक कल्याण के बुनियादी दिशानिर्देशों का पालन करें और सही तरीके से चींटियों को भोजन खिलाएँ, ताकि हमारी कोशिशें केवल अच्छे कर्मों का ही परिणाम लाएँ।

indiangreenbuddy@gmail.com

X@GreenBuddy2024



पके ही नहीं कच्चे केले भी होते हैं सेहत के लिए वरदान, फायदे जान लिए तो बिना खाए नहीं रह पाएंगे आप

केले कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिन्हें खाने से सेहत को ढेरों फायदे मिलते हैं।

आमतौर पर लोग पके केले खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पके केले की ही तरह कच्चे केले भी आपकी सेहत को फायदा पहुंचाता है। इन्हें खाने से किडनी फंक्शन बेहतर होता है और बालों और रिक्त को भी फायदा पहुंचाता है।

पोषक तत्वों से भरपूर केले हमारी सेहत को कई तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं। इन्हें खाना सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को केला खाने की सलाह देते हैं। इन्हें खाने से दिल की सेहत दुरुस्त होती है और डाइजेशन भी बेहतर होता है। इसके अलावा सेहत के साथ ही केले त्वचा और बालों को भी फायदा पहुंचाते हैं।

आमतौर पर केले को पकाकर ही खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पके केले की ही तरह कच्चे केले भी सेहत के लिए काफी गुणकारी होते हैं। इन्हें खाने से भी सेहत को ढेरों फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कच्चे केले के कुछ हैरान करने वाले फायदों के बारे में किडनी फंक्शन को सपोर्ट करे कच्चे केले हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट

बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। ऐसे में इन्हें खाने से किडनी की पूरी फंक्शनिंग में मदद मिलती है और ये किडनी के कैल्शियम को रोकने में मदद कर सकते हैं।

पाचन में सहायता करे कच्चे केले डाइटरी फाइबर का एक अच्छा स्रोत होते हैं, जो पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं। ऐसे में इसे खाने से ब्लोटिंग, कब्ज, दस्त और पेट से संबंधित अन्य समस्याओं से से राहत मिल सकती है।

ब्लड प्रेशर बनाए रखे पोटेशियम से भरपूर होने की वजह से कच्चे केले ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा कच्चे केले स्ट्रोक और दिल के दौरों के खतरे को भी कम कर सकते हैं।

प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को बढ़ावा दे हेल्दी रहने के लिए गट हेल्थ का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है और आंत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बेहद जरूरी हैं। ऐसे में कच्चे केले इन गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जो पाचन तंत्र और पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

मेटाबोलिज्म में सुधारे जरूरी पोषक तत्वों के कच्चे केले फाइबर का भी अच्छा स्रोत होते हैं, जो मेटाबोलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। इन्हें खाने से कैलोरी बर्न करने और वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है।

संस्कारशाला: एक बेहतर पुस्तक प्रेमी बनने के लिए प्रेरणा

डॉ. अंकुर शरण

पुस्तक मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जो ज्ञान, विचार और प्रेरणा का भंडार बनती है। यह न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है बल्कि हमारे जीवन को बेहतर ढंग से समझने का मौका भी देती है। कई सफल व्यक्तियों ने पढ़ने को अपनी आदत बना लिया है, जो उनके जीवन और करियर को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए, कुछ ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियों को जानें, जिन्होंने अपनी पढ़ने की आदत से सफलता के शिखर को छुआ।

1. वॉरेन बफेट: निवेशक और परामर्शदाता
वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिना जाता है, अपनी अत्यधिक पढ़ने की आदतों के लिए जाने जाते हैं। वह प्रतिदिन घंटों तक पढ़ते हैं, जिसमें व्यावसायिक समाचार पत्र, वार्षिक रिपोर्ट और निवेश से जुड़ी किताबें शामिल हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि, रजान चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ही तेजी से आपका ज्ञान बढ़ेगा। [उन्होंने पढ़ने का सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है।]

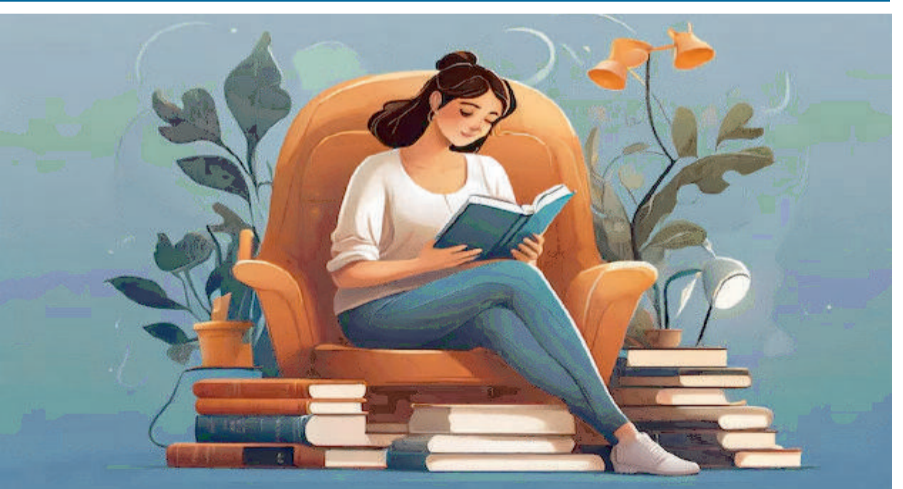
2. ओपरा विफ्रे: टेलीविजन होस्ट और उद्यमी
ओपरा विफ्रे एक शौकीन पाठक हैं, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक क्लब के माध्यम से लाखों लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि पढ़ाई से ही उन्होंने आत्मविश्वास पाया और मुश्किलों का सामना करने की ताकत जुटाई। ओपरा



कहती हैं, रकिताबें हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। वे हमें वह शक्ति देती हैं जिसकी हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरत होती है।

3. एलोन मस्क: तकनीकी उद्यमी और भविष्यवादी
एलोन मस्क, जिन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, छोटी उम्र से ही एक शौकीन पाठक रहे हैं। उन्होंने साक्षात्कारों में बताया कि वह बचपन में प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ते थे। उनका कहना है, रमैन रॉकेट विज्ञान और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में ज्यादातर जानकारी किताबों से प्राप्त की है। यह साबित करता है कि किताबें किसी भी क्षेत्र में गहन ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं।

4. बिल गेट्स: प्रौद्योगिकी के दिग्गज
बिल गेट्स एक उत्साही पाठक हैं और अक्सर अपने ब्लॉग 'गेट्स नोट्स' के माध्यम



से पढ़ी गई किताबों की सिफारिशें साझा करते हैं। वह प्रौद्योगिकी, विज्ञान, उपन्यासों और जीवनियों के प्रति गहरा रूचि रखते हैं। बिल गेट्स का मानना है कि पढ़ने से हमें न केवल दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारे भीतर में मदद करती है, जो हमारे समाज का सामना कर रही हैं।

5. शेरिल सैंडबर्ग: फेसबुक की सीओओ
शेरिल सैंडबर्ग अपनी अनुशासित पढ़ने की आदतों के लिए जानी जाती हैं। वह हर दिन पढ़ने के लिए समय निकालती हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ी गई किताबों से अंतर्दृष्टि साझा करती हैं। शेरिल का मानना है कि रपढ़ना एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, र जो न केवल हमें नए विचार देती है, बल्कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार करने का मौका भी देती है।

6. मार्क जुकरबर्ग: फेसबुक के सीईओ
मार्क जुकरबर्ग ने हर दो हफ्ते में एक किताब पढ़ना अपनी व्यक्तिगत चुनौती बना लिया है। वह मानते हैं कि किताबें उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी सोच है कि रपढ़ना हमें न केवल नए विचारों से जोड़ता है, बल्कि हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करने का भी अवसर देता है।

7. सत्या नडेला: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ
सत्या नडेला को कविता और साहित्य के प्रति गहरा प्रेम है। वह अक्सर साहित्य से सीखे गए पाठों को अपनी नेतृत्व शैली और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। यह दिखाता है कि साहित्य केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।

8. इंद्रा न्यूयी: पेप्सिको की पूर्व सीईओ
इंद्रा न्यूयी एक उत्साही पाठक हैं, जिन्होंने अपनी नेतृत्व शैली को आकार देने का श्रेय किताबों को दिया है। वह अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों को भी निरंतर पढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जिससे वे नए विचारों और दृष्टिकोणों से सीख सकें।

पढ़ने को अपनी आदत बनाएं
इन महान व्यक्तियों की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि पढ़ाई केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है जो हमें सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। पुस्तकें हमें सोचने, समझने और अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। तो क्यों न हम भी इनसे प्रेरणा लेकर पढ़ने को अपनी आदत बनाएं और अपने जीवन तथा करियर को ऊँचाइयों तक पहुंचाएं।

पढ़ें, सीखें, और अपने सपनों को साकार करें!

सत्येंद्र जैन की एक दलील ने जज को किया सोचने पर मजबूर, फिर कोर्ट ने सजा दिया AAP नेता के पक्ष में फैसला

आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत उन्हें मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने और किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की दीपावली अब उनके घर पर ही मनेगी। 18 माह बाद राज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरुआत को उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने और किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अदालत के इस फैसले को सुनकर कोर्ट रुम में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी भावुक हो गईं। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत देते हुए उनकी लंबी हिरासत का हवाला दिया। अदालत ने इसके साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया

गया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। **निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं**

अदालत ने कहा कि सत्येंद्र पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, फिर समाप्त होने की बात तो दूर की बात है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सिंसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार हैं। सत्येंद्र जैन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में करीब 18 माह से जेल में बंद थे।

सत्येंद्र जैन की दलील
सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और विवेक जैन ने उनके मुकदमा के मामले में देरी के आधार पर जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि ईडी पिछले पांच सालों से इसकी जांच कर रही है और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। हरिहरन ने कहा था कि इस मामले में आगे की जांच लंबित है।

उन्होंने कहा था कि इस मामले में डिफाल्ट जमानत आवेदन हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया 17 माह तक हिरासत में रहे और उन्हें जमानत मिल गई। बीआरएस नेता के कविता को पांच माह में जमानत मिल गई। अधिवक्ता ने दलील दी थी कि मामले में उनके मुकदमा को जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित करने की कोश

आशंका नहीं है और न ही उनके मुकदमा के भागने का भी कोई खतरा है। अधिवक्ता ने दलील दी थी कि ईडी की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद यह दूसरी जमानत याचिका दायर है।

हरिहरन ने दलील दी थी कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) 2017 में पंजीकृत हुआ था। पांच साल बाद ईडी ने वर्ष 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की। हरिहरन ने तर्क दिया कि सीबीआई कहती है कि अपराध की आय 1.27 करोड़ रुपये है और ईडी कहती है कि अपराध की आय 4.81 करोड़ रुपये है। हरिहरन ने तर्क दिया था कि ईडी केवल उस हिस्से की जांच कर सकता है, जिसे सीबीआई अपराध की आय कहती है।

ईडी की दलील
ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपनी तरफ से मजबूत दलीलें पेश कर सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया था। अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि अगर सत्येंद्र जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

येथामामला
ईडी का मामला वर्ष 2017 में सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ कार्य से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2015 और 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इसके बाद ईडी ने



शुरुआती छानबीन के बाद मामला दर्ज किया और फिर बाद में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियों बनाकर 4.81 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की।

ईडी को शुरुआती जांच में पता चला कि जैन और उनकी पत्नी की इन कंपनियों में एक तिहाई हिस्सेदारी थी। दोनों जांच दिल्ली के औद्योगिक, बवाना, कराला और मोहम्मद मानवी गांवों में वर्ष 2010 और 2016 के बीच 200 बीघे से ज्यादा जमीन की खरीद पर आधारित है। ये खरीदारी जैन और उनके परिवार के सदस्यों की फर्जी द्वारा की गई। ईडी ने जैन के साथ-साथ उनकी पत्नी पूनम और बिजनेस सहयोगी अजीत प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनील जैन और वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित

बनाया था। ईडी ने आरोप लगाया था जैन ने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थीं। ईडी ने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करते हुए कहा था कि वर्ष 2015-16 के दौरान, सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली इन कंपनियों को कुछ शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। हवाला रूट के जरिए कोलकाता के एंटी आउटरींग कोर्टों को ट्रांसफर किए गए केश के बदले इन सुखौटा कंपनियों से यह रकम प्राप्त हुई। इस धनराशि का इस्तेमाल दिल्ली और आसपास कृषि योग्य जमीन खरीदने को लेकर लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए किया गया।

कब क्या हुआ
24 सितंबर 2017 - सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। चार कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप। ईडी ने भी जांच शुरू की।

2018 - ईडी ने सत्येंद्र जैन को समन कर पूछताछ की। सीबीआई ने भी पूछताछ की।

23 जनवरी 2022 - पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है।

5 अप्रैल 2022 - ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से जुड़ी पांच कंपनियों की 4.8 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की।

30 मई 2022 - ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया।

17 नवंबर 2022 - ट्रायल कोर्ट से सत्येंद्र जैन

की जमानत याचिका खारिज की।

6 अप्रैल 2023 - दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की।

26 मई 2023 - सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।

24 जून 2023 - सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी।

6 नवंबर 2023 - सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ाई।

14 दिसंबर 2023 - सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आठ जनवरी 2024 तक बढ़ाई।

18 मार्च 2024 - सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से किया इन्कार, अंतरिम जमानत भी की रद्द और तत्काल तिहाड़ जेल में सरेडर करने को कहा।

25 जून 2024 - दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफाल्ट जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।

19 सितंबर 2024 - सत्येंद्र जैन राज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश को अदालत में पेश हुए।

और उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इसपर कोर्ट ने 25 सितंबर तक ईडी से जवाब मांगा।

25 सितंबर 2024 - ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

5 अक्टूबर 2024 - सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ऑस्कर विजेताओं के साथ बनी विनोद कापड़ी की नई फिल्म "पायर" (चिता) का वर्ल्ड प्रीमियर यूरोप में

सुषमा रानी

ऑस्कर विजेताओं के साथ बनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता विनोद कापड़ी की नई फिल्म "पायर" (चिता) का वर्ल्ड प्रीमियर, यूरोप के प्रतिष्ठित 28वें टैल्लिन ब्लैक नाइट्स अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में होगा। इस साल टैल्लिन में चुनी गई ये अकेली भारतीय फिल्म है। फिल्म को वर्ल्ड कपीटेशन श्रेणी में रखा गया है और प्रीमियर की तारीख 19 नवंबर 2024 तय हुई है। टैल्लिन की तरफ से आज ही दुनिया भर से चुनी गई फिल्मों की सूची जारी हुई है।

"पायर" उत्तराखंड के हिमालय की पृष्ठभूमि में रची 80 साल के दो बुजुर्गों की एक अद्भुत, अनोखी, कलेजा चीर देने वाली अविश्वसनीय प्रेम कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि लेखक - निर्देशक विनोद कापड़ी ने फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर उन दो बुजुर्गों को पदम सिंह और हीरा देवी को कास्ट किया है, जिन्होंने फिल्म की शूटिंग से पहले जीवन ना कभी कोई कैमरा देखा है, ना ही कोई फिल्म। पदम सिंह और हीरा देवी दोनों ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनास तहसील के रहने वाले हैं। पदम सिंह पहले भारतीय सेना में थे और रिटायरमेंट के बाद खेतीबाड़ी करते हैं जबकि हीरा देवी घर में भैंस पालने और जंगल से लकड़ी और घास

काटने का काम करती हैं।

डायरेक्टर विनोद ने पहले इस फिल्म के लिए नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह Shah को कास्ट किया था। दोनों तैयार भी हो गए थे। लेकिन फिर नसीर साहब ने विनोद के सामने एक संशय रखा कि हिमालय की कहानी में नसीर/रत्ना की casting से फिल्म की प्रमाणिकता पर अंतर पड़ सकता है। विनोद ने फिर नए सिरे से कास्टिंग शुरू की और हिमालय के दूर दराज के दो दर्जन से ज्यादा गाँवों में तीन महीने तक भटकने के बाद विनोद को उनके पदम सिंह और तुलसी देवी मिल ही गए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी भी कैमरे का सामना नहीं किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अनुप त्रिवेदी के मार्गदर्शन में दो महीने तक चली वर्कशॉप के बाद दोनों कलाकार शूटिंग के लिए तैयार किए गए।

खास बात ये भी है कि Pyre की शूटिंग पूरी होने पर फिल्म की फुटेज देखने के बाद ऑस्कर विजेता फिल्म संगीतकार माइकल डैन्ना तुरंत "पायर" के लिए संगीत करने को तैयार हो गए। माइकल को "लाइफ ऑफ पाई" के लिए 2012 में



ऑस्कर मिला था। जर्मन एडिटर पैट्रिशिया रॉमेल ने फिल्म को एडिट किया है। पैट्रिशिया ने ही "दि लाइफ ऑफ अदर्स" फिल्म को एडिट किया था, जिसे 2006 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का ऑस्कर मिला था। भारत के विलक्षण गीतकार और "जय हो" जैसे गीत लिख चुके गुलजार ने "पायर" के लिए एक गीत लिखा है।

विनोद के मुताबिक - ये उनका परम सौभाग्य है कि विश्व सिनेमा की इन तीन महान हस्तियों ने "पायर" में अपना योगदान दिया है। माइकल और पैट्रिशिया ने तो अपनी फ्रीस 90 फ्रीसदी तक काम कर दी और गुलजार साहब ने तो फ्रीस तक लेने से मना कर दिया। गुलजार सर ने यहाँ तक कहा कि जिस सिनेमा में उन्हें सत्यजीत राय के सिनेमा की झलक दिख रही हो, उसमें वो फ्रीस कैसे ले सकते हैं ?

यह फिल्म "पायर" उत्तराखंड में लगातार हो रहे पलायन के बाद वहाँ खाली हो चुके गाँव, जिन्हें भूतिया गाँव भी कहा जाता है - को पृष्ठभूमि में एक बुजुर्ग दंपति की सच्ची कहानी से प्रभावित है, जिसे विनोद 2017 में मुनस्यारी के एक गाँव में मिले थे। मृत्यु का इंतजार कर रहे इस बुजुर्ग दंपति के एक दूसरे को लेकर प्यार ने विनोद के दिल में ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने ये फिल्म बनाने का फैसला किया।

नॉन एक्टर की इस फिल्म को बनाने के लिए जब कोई निर्माता नहीं मिला तो विनोद ने अपने और पत्नी साक्षी जोशी ने खुद ये फिल्म बनाने का फैसला किया। भागीरथी फिल्म की निदेशक साक्षी जोशी का कहना है कि "कहानियों और किरदारों को लेकर विनोद के संकल्प पर उन्हें हमेशा से भरपूर रहा है। भारत में स्टूडियो के सहयोग के बिना स्वतंत्र फिल्म बनाना मुश्किल काम होता है, लेकिन असंभव नहीं है।"

टैल्लिन ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद कम से कम 7-8 महीने तक "पायर" अलग अलग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में चलेगा और उसी के बाद फिल्म को भारत में रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने आज फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी किया है।

नोएडा फिल्म सिटी में मारवाह स्टूडियो के ऐतिहासिक दौरे में



सुषमा रानी

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने डॉ. संदीप मारवाह के पिता के सम्मान में नामित नए सूरज प्रकाश मारवाह शूटिंग फ्लोर का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर ने मारवाह स्टूडियो की विरासत में एक नया अध्याय जोड़ा है। डॉ. मुरुगन ने जहाँ व्यक्तिगत रूप से स्टूडियो, पोस्ट-प्रोडक्शन इकाइयों, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीसीसी) डिवीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विशाल पुस्तकालय, एम्पीथिएटर, स्क्रीनिंग थिएटर, ललित कला विभाग और शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं

सहित सुविधाओं और विभागों को देखा व भूरि भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर मारवाह स्टूडियो के अध्यक्ष डॉ. संदीप मारवाह ने इस अवसर पर डॉ. मुरुगन को स्टूडियो की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें उनकी कई उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करने वाली पुस्तकों का संग्रह भी शामिल था। अत्याधुनिक सुविधाओं और उद्योग में मारवाह स्टूडियो के योगदान से प्रभावित होकर, डॉ. मुरुगन ने, न केवल नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना में बल्कि क्षेत्र में फिल्म, टेलीविजन और मीडिया व्यवसाय को आकार देने में डॉ. मारवाह की दूरदर्शी भूमिका के लिए अपनी प्रशंसा की। डॉ. एल.

मुरुगन ने कहा, मारवाह स्टूडियो फिल्म और मीडिया उद्योग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में खड़ा है और डॉ. संदीप मारवाह के योगदान ने इस क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाया है। यहाँ की सुविधाएँ विश्व स्तरीय हैं और रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण वास्तव में सराहनीय हैं। डॉ. संदीप मारवाह ने डॉ. मुरुगन को उनके उत्साहवर्धक शब्दों और सूरज प्रकाश मारवाह शूटिंग फ्लोर का उद्घाटन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह रचनात्मकता और उत्पादन उत्कृष्टता के लिए एक नए केंद्र के रूप में काम करेगा।

एन एस ई आर डी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई

सुषमा रानी

नई दिल्ली : एन एस ई आर डी ने महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में वाल्मीकि जयंती के सम्मान में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागियों द्वारा फूलों की माला अर्पित करने के साथ हुई, इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाणिज्य विभाग के प्रमुख प्रो. डी. के. धुसिया ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डाला और साथ ही रामायण के उनके लेखक होने पर प्रकाश डाला, जिसे वाल्मीकि रामायण के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वाल्मीकि के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे योग वशिष्ठ और वाल्मीकि संहिता का भी उल्लेख किया और कहा कि वाल्मीकि राम और सीता के पुत्रों लव और कुश के गुरु थे।

प्रो. धुसिया ने भारतीय साहित्य में वाल्मीकि के अपार योगदान पर जोर दिया। एनएसईआरडी के अध्यक्ष मोहम्मद कैफ ने



वाल्मीकि की शिक्षाओं, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संगठन के समर्पण की पुष्टि की। इस कार्यक्रम में पारंपरिक सजावट और संवादात्मक सत्र

शामिल थे, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और महर्षि वाल्मीकि के शाश्वत ज्ञान को फैलाने के लिए एन एस ई आर डी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया, खास तौर पर महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। एन एस ई आर डी की निदेशक सुश्री मोनिका त्यागी ने सभी का धन्यवाद किया।

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर खुशी फाउंडेशन चैरिटेबल सोसाइटी एवं वैष्णवी फाउंडेशन और मोहल्ला परिवार समिति निवासी कल्याण संघ आरडब्ल्यूएफएस्ट ब्लॉक मदनगढ़ में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती

पर मालापूर्णा किया गया। समारोह में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी किया गया और यह नेत्र जांच शिविर फाउंडेशन चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्ष गीता यादव, उपाध्यक्ष आशीष मैसी एवं उनकी समस्त टीम द्वारा किया गया। जिसमें 250 से अधिक लोगों ने अपनी आँखों की जांच

करवाने के साथ शुगर एवं बीपी की भी जांच करवाई।

इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि खानपुर से निगम पाठक ममता यादव मदनगढ़ के निगम पाठक गीता संजय जी, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा चंद्रपाल बैरवा, अधिवक्ता राज कुमार गोवाल,

समाज सेवक दिलीप कुमार देवतवाल, मेधा मिथिलेश, समाज सेवक आशीष करोटिया, मिशन सहयोगी एनजीओ के अध्यक्ष नितिन वर्मा, गुलशन करोटिया, सूरज जी, विशाल जी, आकाश जी, नदीम जी, इस कार्यक्रम में शामिल रहे। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला।

उत्तर प्रदेश के उप-चुनाव में भी भाजपा हिंदुत्व एवं राष्ट्रवाद के सहारे

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव में यूपी में मनमाफिक नतीजे नहीं आने से दुखी बीजेपी को अगर हिंदुत्व के सहारे उप चुनाव में सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर पार्टी का आलाकमान रणनीति बनाई जायेगा।

इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भले ही संविधान, आरक्षण और जातीय समीकरण साध कर बीजेपी को हिंदुत्व की राह में रोड़े बिछा दिये थे, लेकिन कहते हैं कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है और हाल ही में सम्पन्न हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधान सभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व ने एक बार फिर हुंकार भरी और कांग्रेस के हरियाणा में सरकार बनाने के सपने चूर-चूर हो गये। इसी से उत्साहित बीजेपी अब यूपी के उप चुनाव में भी हिंदुत्व की पंच पर बैटिंग करने का मन बना चुकी है। जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा फिर हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल करेगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव का फायदा भाजपा यूपी के उपचुनाव में भी उठाना चाहती है। पार्टी का भी मानना है कि हिंदुत्व के फार्मूले से जातीय समीकरण साधने में उसे मदद मिलेगी। भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की नौ विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फार्मूले का परीक्षण करेगी।

लोकसभा चुनाव में यूपी में मनमाफिक नतीजे



नहीं आने से दुखी बीजेपी को अगर हिंदुत्व के सहारे उप चुनाव में सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर पार्टी का आलाकमान रणनीति बनाई जायेगा। दरअसल, हरियाणा में लगातार तीसरी बार और 2014 व 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का सपना भाजपा के लिए बड़ा चुनौती बन चुका है। वहाँ, जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का कश्मि भाजपा भले ही नहीं कर पाई हो, लेकिन वहाँ मिले सबसे ज्यादा वोटों ने पार्टी में नई उम्मीद जगाई है।

लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में आए नतीजों को कांग्रेस ने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति से विदाई के तौर पर प्रचारित किया। अब हरियाणा और जम्मू-कश्मीर ने इसे एक तरह से खरिज कर दिया

है। साफ है कि अब भाजपा यूपी के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगी। इसका असर प्रदेश में दिखने भी लगा है। हालाँकि, भाजपा के एजेंडे को काठ को लेकर कांग्रेस और सपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है।

बता दें हरियाणा की तरह जम्मू-कश्मीर में भी ज्यादातर हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद दिखे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, हिंदू लामबंदी जिस तरह जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ती दिखी है, वह यह बताते हैं कि पर्याप्त है कि बंटोगे तो कटोगे के नारे ने नतीजों पर असर डाला है। जाहिर है कि भाजपा इसे और धार देगी ताकि यूपी में 2014 से लेकर 2022 जैसे समीकरणों को फिर मजबूत किया जा सके।

योगी सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर को लेकर जारी किया बड़ा आदेश, ये हैं नियम और शर्तें

लिफ्ट व एस्केलेटर स्वामी के लिए एक जरूरी खबर है। योगी सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर लिफ्ट व एस्केलेटर स्वामी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया गया कि जिलाधिकारी के पास शासनादेश आ गया है। जिसमें औपम्यकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सोसायटीज, सेक्टर सहित बड़े मॉल, कार्यालयों में लिफ्ट व एस्केलेटर की सुरक्षा, अनुरक्षण, संचालन के लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024 को 25 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया गया है। इसको लेकर डीएम के पास शासनादेश आ गया है। इसमें डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एडीएम वित्त एवं राजस्व, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। यह सदस्य लिफ्ट व एस्केलेटर

संबंधित अनुरक्षण, सुरक्षा व संचालन को लेकर हो रही गतिविधियों, किसी दुर्घटना पर समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को देगे।

सुरक्षा को लेकर किया था खबर का प्रकाशन
मंगलवार के अंक में लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर खबर का प्रकाशन किया था कि शासनादेश जारी न होने से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण की तरफ से 25 सितंबर 2024 को जारी शासनादेश में नियम नौ में प्रविधान किया गया है कि लिफ्ट, एस्केलेटर से संबंधित दुर्घटना लागूबुक अनुरक्षित करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी संचालक की होगी। यह लागूबुक आधिकारिक तौर पर स्थानीय सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा या अधिकारिता वाले किसी अन्य विद्युत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से अधिकृत किसी कार्यकारी अधिकारी के मांगे जाने पर इसे देना होगा। गठित की गई पांच सदस्यीय समिति की त्रैमासिक बैठक की जाएगी।

यह है शासनादेश
उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 26 फरवरी 2024 को अधिनियम लागू किया गया था। वहीं 18 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी की गई। शासनादेश में प्रमुख रूप से हर लिफ्ट व एस्केलेटर

स्वामी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अधिनियम की धारा-10 में प्रदेश में पहले से ही संचालित लिफ्ट, एस्केलेटर का अधिनियम लागू होने के छह माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है।

नियम सात के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण कमीशनिंग एजेंसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इनका वार्षिक अनुरक्षण एजेंसी की तरफ से कराए जाने की व्यवस्था दी गई है। साथ ही इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर विलंब शुल्क का प्रविधान है।

लिफ्ट व एस्केलेटर के लिए सरकार का आदेश जारी

शासनादेश आज ही मिला है। इसमें जो भी नियम हैं उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024-25 सितंबर से प्रभावी हो चुकी है। इसके अनुसार ही जिलों में लिफ्ट व एस्केलेटर संचालकों को कार्य करना होगा। इनके अनुरक्षण, रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। दुर्घटना की स्थिति में पांच सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देगी। नियमावली के लागू होने से प्रशासन को कार्रवाई करने में आसानी होगी और लोगों को न्याय मिल सकेगा। - मनीष कुमार वर्मा,

न चोरी हुई न डाका पड़ा, बैंक की तिजोरी से 5 लाख के नोट गायब, अधिकारियों ने खोलकर देखा लॉकर तो उड़ गए होश

नोएडा के सिटीजन को अपरेंटिव बैंक में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। बैंक के लॉकर में रखे पांच लाख रुपये के नोट दीमक ने चट कर दिए। इतना ही नहीं लॉकर में रखे आभूषण के डिब्बे भी दीमक ने चट कर दिए। लॉकर होल्डर ने इस मामले में शाखा प्रबंधक से शिकायत की है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरा मामला।

नोएडा। नोएडा में सेक्टर-5 स्थित सिटीजन को अपरेंटिव बैंक के लॉकर में रखे पांच लाख रुपये व आभूषणों के डिब्बे दीमक ने चट कर दिए। लॉकर होल्डर ने जब इस मामले की शाखा प्रबंधक से शिकायत की तो उन्होंने आरबीआइ की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। रुपयों में दीमक लगने की वजह दीवार में आई सीलन को बताया जा रहा है।

लॉकर होल्डर के मुताबिक, उनके लॉकर में पांच लाख रुपये रखे हुए थे। दो-तीन दिन पहले जब वह रुपये निकालने गए तो सारे रुपयों में दीमक लग चुके थे। इसमें दो लाख रुपये के नोट पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, जबकि तीन लाख रुपये के नोट में जगह-जगह छेद हो गए थे, जो बाजार में चल नहीं सकते।

बॉक्स भी दीमक ने खत्म कर दिया
इसके अलावा कीमती आभूषण का बॉक्स भी दीमक ने खत्म कर दिया था। यह तीन लाख रुपये आरबीआइ से बदलवाने के लिए लॉकर होल्डर ने शाखा प्रबंधक पर दबाव बनाया। इसके बाद बैंक ने आन्य ग्राहकों से भी लॉकर चेक करने के लिए संपर्क किया।

इसके बाद दो दिन में कई लोग अपना लॉकर चेक करने बैंक पहुंच चुके हैं। एक अन्य लॉकर होल्डर ने भी नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बैंक ने फोन कर उनसे संपर्क किया और लॉकर चेक करने के लिए कहा है।

हिंदुओं के त्योहार पर ही क्यों फैलती हैं अराजकता और हिंसा ?

संजय सक्सेना

हालात यह है कि हिंदुओं के छोटे से छोटे धार्मिक आयोजन भी बिना पुलिस की सुरक्षा के घेरे के पूर्ण नहीं हो पाते हैं। हिंदुओं के देवी-देवताओं को कभी कला के तो कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपमानित किया जाता है।

यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहां की बहुसंख्यक आबादी को अपने तीज-त्योहार मनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुओं के द्वारा कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता है उस पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का साथ पड़ जाता है। हिन्दू जब भी कावड़ यात्रा निकाले, माता का जागरण कराये, मूर्तिविसर्जन को जाये या इसी तरह के अन्य कोई आयोजन करे तो मुस्लिम कट्टरपंथी कहीं उस पर पथराव करने लगते हैं तो कहीं रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। उनके इस क्रूरता का विरोध होता है तो यह लोग तलवारें बांजने लगते हैं। आगजनी और पेट्रोल बम फोड़ने वाले तब जरूर आहत हो जाते हैं जब उन्हें कहीं पटाखों की आवाज सुनाई पड़ जाती है।

हालात यह है कि हिंदुओं के छोटे से छोटे धार्मिक आयोजन भी बिना पुलिस की सुरक्षा के घेरे के पूर्ण नहीं हो पाते हैं। हिंदुओं के देवी-देवताओं को कभी कला के तो कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपमानित किया जाता है। न जाने क्यों पांच टाइम लाउडस्पीकर पर चीखने चिल्लाने वालों को हिन्दुओं के धार्मिक आयोजनों में बजने वाला डीजे बचने क्यों कर देता है। इसी तरह से होली के रंग-गुलाल भी एक वर्ग विशेष के चंद कट्टरपंथियों के चलते साध्यताधिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यह कट्टरपंथी तभी भड़कते हैं जब हिन्दुओं के द्वारा अपना कोई धार्मिक जुलूस आदि दिखाने जाते हैं। यदि उस लाकर से संबंधित कोई विवाद होता है, तो जांच एजेंसी अपने सामने लाकर खुलवाकर जांच करती है।

पहुंच कर माहौल खराब करने से नहीं हिचकते हैं। इतना ही कई बार तो इन अराजक तत्वों को वोट बैंक की राजनीतिक करने वाले नेताओं और पार्टियों का राजनैतिक संरक्षण भी मिल जाता है। यदि ऐसा होता तो बहराइच में बेरहमी से मारे गये रामगोपाल मिश्र की हत्या पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक्स पर वह कथित वीडियो नहीं पोस्ट करते जिसमें रामगोपाल मिश्र एक मुस्लिम परिवार के घर से हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहा है। अखिलेश इस वीडियो के सहारे रामगोपाल मिश्र को ही कट्टरपंथ में खड़ा कर रहे हैं, जबकि इसका कानूनी पहलू यह है कि यदि रामगोपाल मिश्र ने हरा झंडा उतार कर वहां भगवा झंडा फहरा ही दिया था तो हत्यारों को उसका कत्ल करने की छूट नहीं मिल जाती है। रामगोपाल मिश्र को मारा ही नहीं गया, उसके साथ हत्यारों ने वधशोषण दिखाते हुए रामगोपाल के नाखून तक बेरहमी के साथ नोच लिये थे।

ज्यादा पीछे न भी जाया जाये तो हालफिलहाल में ही इस्लामी कट्टरपंथियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा और हिन्दुओं को निशाना बनाया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहीं पंडाल पर पथराव किया गया तो कहीं मूर्तिविसर्जन के जुलूस पर हमला हुआ, जुलूस के रस्तों को लेकर भी विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक पथराव और हिंसा हुई है। यह हिंसा हिन्दुओं के त्योहार नवरात्र के साथ ही चालू हो गई थी। हावड़ा के श्यामगंज में 13 अक्टूबर, 2024 को एक मुस्लिम भीड़ ने हिन्दू पंडालों पर हमला किया। मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडालों को नष्ट करना चाहू कर दिया। उन्होंने मूर्तियों को आग लगा दी और कई पंडालों को तबाह किया। यह मुस्लिम भीड़ उस घाट पर भी पहुंची जहाँ देवी मूर्तियों का विसर्जन होना था। यहाँ इस भीड़ ने पथराव किया।

बात विशेषकर उत्तर प्रदेश की कि जाये तो यहां के कौशांबी जिले में माँ दुर्गा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में जुलूस में शामिल

महिला श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गईं और पत्थरबाजी हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटें आईं। 12 अक्टूबर, 2024 को हुए इस हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय के लगभग एक दर्जन लोगों पर लगा है जिसमें खतूनतों भी शामिल हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसी तरह से बलरामपुर में दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपितों में कलीम, अरबाब, इमरान और मुख्तार शामिल थे, जिन्होंने महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता की और पंडाल में लगे भगवा ध्वज को तोचकर नाली में फेंक दिया। महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जिला गोंडा के मसकनवा बाजार इलाके में 9 अक्टूबर, 2024 को दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के बाद देवी की आँखों पर से पट्टी हटाई गई थी। इस मूर्ति की स्थापना बोते कई सालों से की जाती है। इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में हिन्दू इकट्ठा थे पूजा अर्चना के बाद कुछ हिन्दू बच्चे इस पंडाल के बाहर पटाखे फोड़ने लगे। पटाखों की आवाज सुन कर पास में रहने वाले मुस्लिम भड़क गए। मुस्लिम परिवार के लोग बाहर निकल कर हिन्दुओं को गालियाँ देने लगे और हमलावर हो गए। उन्होंने पहले हिन्दुओं पर पथराव किया और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उधर, कुशोनगर में एक और गंभीर घटना सामने आई, जब दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मूर्ति पर पथराव किया। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आरोपितों को गिरफ्तार किया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। हिन्दू समुदाय ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की। अब बहराइच की हिंसा इसका नया उदाहरण

है जहाँ मूर्तिविसर्जन के लिये जा रहे एक व्यक्ति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। यह जानकारी देते ही मूर्तिविसर्जन के लिये जा रहे लोगों में सामने आई है या जिनकी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ को देखते हुए कहा जा सकता है कि कई घटनाएँ संभवतः बाकी शोर शराब में अलग हो रही हैं।

कुल मिलाकर कट्टरपंथियों की जेहादी सोच के कारण पिछले कुछ वर्षों से शोभा यात्राओं या फिर प्रतिमा विसर्जन यात्राओं का शांतिपूर्ण माहौल में निकलना कठिन होता जा रहा है। इन धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी कई बार दंगों का रूप धारण कर लेती है, जैसा कि बहराइच में हुआ। यहाँ दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा पर घरों की छतों से पथराव हुआ। एक सतानी की की हत्या कर दी गई और उसके बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। प्रश्न यह है कि जब यह सब हो रहा था, तब पुलिस कहाँ थी? पुलिस की अकर्मण्यता की वजह से ही दूसरे दिन युवक के अंतिम संस्कार को पहले फिर हिंसा भड़क उठी और उग्र लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और दुकानें जला दीं। यह ठीक है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद हिंसा पर काबू पर लिया गया, लेकिन अहम प्रश्न यह है कि क्या सद्भाव के मौहल की वापसी हो सकेगी और उन तत्वों को सबक सिखाने वाली ठोस कार्रवाई हो सकेगी, जिनके कारण हिंसा का सिलसिला कायम हुआ?

सबसे दुःख यह है कि इस तरह की किसी भी घटना के बाद कुछ लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि अमुक क्षेत्र से यात्रा निकाली ही क्यों गई। किसी भी क्षेत्र को हिन्दू-मुस्लिम क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना क्या उचित है। दरअसल, हिन्दू-मुस्लिम क्षेत्र की बातें ही विभाजनकारी और शरारत भरा एजेंडा है। ऐसे एजेंडे आम तौर पर वोट बैंक की राजनीति के तहत चलाए जाते हैं। इस एजेंडे की काट के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसी भी समुदाय के धार्मिक आयोजन हिंसक तत्वों को शिकार न बनने पाएँ।

हिन्दू पर्वों से इतनी नफरत क्यों और उन पर हमले कब तक ?

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है, प्रदेश की सशक्त कानून व्यवस्था के कारण ही न केवल योगी सरकार पुनः सत्ता में आई है वरन उसका प्रभाव अन्य प्रान्तों की चुनावी राजनीति पर भी पड़ रहा है।

हिंदू पर्वों नवरात्र व विजयादशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में जिस प्रकार दुर्गा प्रतिमाओं को खंडित करके अपमानित किया गया, मूर्ति विसर्जन में बाधा डाली गई, शोभा यात्राओं पर हमले किये गए, उससे निन्दनीय कृत्य नहीं हो सकते। इससे भी निन्दनीय है मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए एकतरफा विकृत बयानबाजी करके उस हिंसा का बचाव किया जाना। स्वतंत्रता के बाद के इतने वर्षों में हिंदू समाज के लोगों ने कभी भी किसी भी मजहब के पर्वों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला वरन सदा सहिष्णुता का परिचय देते हुए उनके पर्वों को मनाने में सहयोग ही किया है। इसके विपरीत मुस्लिमान कभी भी हिन्दुओं को उल्लास, उत्साह और प्रसन्नता के साथ कोई पर्व मनाने नहीं देते हेमेश्या पत्थर, बोटल, और बम लेकर हमले के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा ?

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है, प्रदेश की सशक्त कानून व्यवस्था के कारण ही न केवल योगी सरकार पुनः सत्ता में आई है वरन उसका प्रभाव अन्य प्रान्तों की चुनावी राजनीति पर भी पड़ रहा है। दूसरी तरह कुछ राजनैतिक दल और उनका वोट बैंक हर दिन प्रदेश की मानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इसी वोट बैंक



ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पूर्व नियोजित रूप से पथराव करके वातावरण बिगाड़ने में कामयाबी पा ली और निर्दोष राम गोपाल मिश्रा को अपने प्राण गंवांने पड़े।

शांति भंग करने का प्रयास केवल बहराइच में ही नहीं हुआ, विजयादशमी के पूर्व ही समुदाय विशेष ने लखनऊ और आजमगढ़ में देवी प्रतिमाओं को खंडित कर वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया। लखनऊ में प्रतिष्ठित मरी माता मंदिर में देवी प्रतिमा को खंडित किया गया, आजमगढ़ में मां लक्ष्मी की प्रतिमा को खंडित किया

गया, गोंडा जिले में दुर्गा पंडाल के बाहर पत्थरबाजी की गई, हरदोई जिले में भी अरजकतत्वों ने नवरात्रि के समय में ही मंदिर में स्थापित देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया जिसके कारण तनाव उत्पन्न हुआ किंतु ग्रामीणों व पुलिस की सतर्कता के कारण जल्द उपद्रव नहीं हो सका। इसी प्रकार रायबरेली जिले के बछराव में चंद्रिका देवी मंदिर में रखी चार मूर्तियां अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दीं। इसी प्रकार अंबेडकरनगर के बेताना में और बाराबंकी के कसबा इचौली में विसर्जन जुलूस के दौरान आपत्तिजनक वस्तु फेंकी गई और उपद्रव करने का

प्रयास किया गया। आजमगढ़ में दूसरी बार निजाामाबाद में विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। यहाँ पर 48 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आगरा के बमरौली कटारा के समोरांग घाट पर यमुना में मूर्ति विसर्जन में बाधा डालने के उद्देश्य से धर्म विशेष के दो युवकों ने चौकी प्रभारी मुकेश कुमार पर हमला बोल दिया। उनका गला दबाया और जमीन पर गिराकर पीटा। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के आने पर ही वह किसी प्रकार से बच सके किंतु यहाँ पर भी लापरवाही के कारण वह

दोनों युवक भाग निकलने में सफल हो गये। बिजनौर जिले में मंदिर से रामचरित मानस को चोरी कर जला दिया गया।

आखिर यह सब मानसिक विकृति नहीं तो और क्या है ? नवरात्र और दुर्गापूजा के अवसर पर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएँ घटी हैं यदि विहंगम दृष्टि डाली जाए तो सबका पैटर्न लगभग एक समान है। यह सभी घटनाएँ देखने व सुनने में छुटपुट जरूर हैं किंतु इनका उद्देश्य सामूहिक है। केंद्र सरकार ने पीएफआई जैसे कुख्यात संगठनों को प्रतिबंधित अवश्य कर दिया है किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि

उनके स्पीपर सेल लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। दुर्गा पूजा, विजयदशमी, रामनवमी, गणेशोत्सव भारतीय संस्कृति और परंपरा के महत्वपूर्ण पर्व हैं, पहचान है हमारी संस्कृति के इनसे या इनको मनाने वालों से किसी को क्या शत्रुता हो सकती है ? बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बाईस वर्षीय हिन्दू युवक राम गोपाल मिश्र बलिदान हो गया, मुसलमानों ने अत्यंत क्रूरता से उसकी हत्या कर दी किंतु प्रदेश में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले इस अवसर पर भी अपने वोट बैंक को साधते दिखाई दिए।

ये मुस्लिम तुष्टिकरण वाले दल पहले सरकार और प्रशासन की विफलता को दोष दे रहे थे और अब जब सख्ती बरती जा रही है तब कह रहा है कि प्रदेश सरकार एकरतफा कार्यवाही कर रही है। अब उन्हें केवल योगी का इस्तीफा चाहिए क्योंकि अब पत्थरबाजों के हिंसाव किताब का समय है। जब दुर्गापूजा और गणेशोत्सव पर ऐसे ही एकरतफा हमले होंगे तो कभी न कभी हिन्दू समाज का धैर्य भी जवाब देगा, यदि हिन्दू समाज भी ऐसा ही करने लगे तो ?

बहराइच की घटना में एक निर्दोष 22 वर्षीय हिंदू युवक की बर्बरता पूर्ण हत्या कर दी जाती है तो मीडिया का एक वर्ग भी अल्पसंख्यकों के पक्ष में मौन धारण कर लेता है लेकिन बाबा सिद्धीकी नाम के अपराधी को तुष्टिकरण करने वालों की कुपा सफेदपोश हो गया उसके लिए एकरतफा कार्यवाही है। ये यह एकरतफा सेकुलरिज्म अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। दूसरी ओर अब हिंदुओं को भी यह बात समझनी होगी कि अपनी सुरक्षा के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, अपने आपको इतना सशक्त बनाना होगा कि कोई भी आपके पर्वों को दुःख के पर्व में बदलने का दुस्साहस करने के बारे में सोच भी न सके।

- मृत्युंजय दीक्षित

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



अब ग्वालियर शहर में 20 अक्टूबर से दो पालियों में चलेंगे ई-रिक्शा, लाटरी से हुआ निर्धारण, इन पर होगी सख्ती



परिवहन विशेष न्यूज

शहर में संचालित ई-रिक्शों को व्यवस्थित तरीके चलाने की कवायद कर रहे ग्वालियर जिला प्रशासन को आखिरकार इसमें सफलता मिल ही गई, गुरुवार, 17 अक्टूबर को ये फैसला हुआ कि ग्वालियर शहर में दो पालियों में ई-रिक्शा चलेंगे। इसके लिए रिक्शों की कलर कोडिंग की गई है साथ ही हिदायत दी गई है कि अब से गैर पंजीकृत और बिना कलर कोडिंग वाले ई-रिक्शा शहर में नहीं चल सकेंगे।

ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं बेहतर बनाने के लिये अहम निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत शहर में 20

अक्टूबर से दो पालियों में ई-रिक्शा चलेंगे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में पच्ची डालकर (लाटरी पद्धति से) ई-रिक्शों के लिए पालियों का निर्धारण किया गया। नन्ही-मुन्नी बालिका कु. जोया द्वारा पच्ची उठाई गई। जिससे तय हुआ कि नीले कलर कोडिंग वाले ई-रिक्शा प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेंगे और पीले कलर कोडिंग वाले रिक्शा अपराह्न 3 बजे से प्रातः 3 बजे तक शहर में चलेंगे। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव एवं स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती नीतू माथुर भी मौजूद थीं।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बताया कि रिक्शा चालकों को व्यवसाय के समान अवसर मिल सकें। इस बात को ध्यान में रखकर दो माह बाद अर्थात् आगामी 20 दिसम्बर को ई-रिक्शों की पालियाँ बदली जायेंगी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बैठक में स्पष्ट किया कि जिन ई-रिक्शों का पंजीयन और कलर कोडिंग नहीं हुई है शहर में ऐसे रिक्शों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे रिक्शा मिलने पर जब्त कर थाने भेजे जायेंगे। बैठक में बताया गया कि ग्वालियर शहर में अब तक 6 हजार 171 ई-रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से लगभग 4 हजार 580 ई-रिक्शों की कलर कोडिंग भी की जा चुकी है।

चीन को पीछे छोड़ भारत बना सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार

परिवहन विशेष न्यूज

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार बन गया है। भारत ने यह मुकाम चीन को पीछे करके हासिल किया है। चीन में लोग हाल के समय में मोटरसाइकिल और स्कूटर की जगह ई-साइकिल का ऑप्शन चुन रहे हैं। हालांकि चीन में 125 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहन लोकप्रिय बने हुए हैं। इस साल की पहली छमाही के दौरान 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नई दिल्ली। चीन को पीछे छोड़ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार बन गया है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग, अनुकूल भ्रानसून की स्थिति और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की पहल इसकी बड़ी वजह है। काउंटरपाइंट रिसर्च के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 2024 की पहली छमाही के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री में चार प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि दर्ज की गई। खास बात यह है कि भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई जबकि चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

चीन में ज्यादा चला रहे ई-साइकिल विश्लेषक सोमने मंडल ने कहा कि भारत के दोपहिया वाहन बाजार में इस साल की पहली छमाही के दौरान 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इस



मजबूत प्रदर्शन ने भारत को चीन से आगे निकलने और दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार बनने में मदद की। भारत में इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दोपहिया वाहन में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि (साल-दर-साल) देखी गई। चीन में 125 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहन लोकप्रिय बने हुए हैं, लेकिन अब वहां के लोग आने-जाने के लिए मोटरसाइकिल और स्कूटर की जगह ई-साइकिल का विकल्प चुन रहे हैं।

गिरावट के पीछे की वजह

उधर, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाइलैंड और मलेशिया में भू-राजनीति तनाव, सख्त ख़ा मानदंड और सतर्क उपभोक्ता खर्च के चलते दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। शीर्ष-10 वैश्विक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल बिक्री का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हासिल किया। वैश्विक

दोपहिया वाहन बाजार में होना ने अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, यामाहा, टीवीएस मोटर और याइया का स्थान रहा। शीर्ष-10 ब्रांडों में टीवीएस मोटर सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड (सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि) रहा। याइया में सबसे ज्यादा गिरावट (सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की गिरावट) गिरावट दर्ज की गई और यह पांचवें स्थान खिसक गई।

चंदौली में नहीं चलेंगे दूसरे जिलों के ई-रिक्शा



परिवहन विशेष न्यूज

चंदौली जिले में गैर जनपदों में पंजीकृत ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर योजना तैयार कर ली है।

ई-रिक्शा की भरमार के कारण पीडीडीयू नगर समेत जिले के विभिन्न कस्बों में रोज जाम लग रहा है। इनमें बड़ी संख्या में गैर जनपद में पंजीकृत ई-रिक्शा शामिल हैं। ऐसे में दूसरे जिलों में पंजीकृत ई-रिक्शा को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

बरेजगारों के लिए कमाई का

साधन होने के कारण जिले में ई-रिक्शा की भरमार हो गई है। गैर जनपद में पंजीकृत ई-रिक्शा भी जिले में चल रहे हैं। परिवहन विभाग में वर्ष 2018 से अक्टूबर 2024 तक 2039 ई-रिक्शा पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में दूसरे जिलों में पंजीकृत ई-रिक्शा जिले में चल रहे हैं।

पीडीडीयू नगर, सकलडीहा, चकिया, चंदौली आदि क्षेत्रों में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। जाम से निपटने के लिए मुख्यमंत्री कबीर अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपना चुके हैं। अब इससे निपटने के लिए

चंदौली जिले में गैर जनपदों में पंजीकृत ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर योजना तैयार कर ली है। जल्द ही जिले के सभी कस्बों में अभियान चलाकर ऐसे ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगाई जाएगी।

पीडीडीयू नगर सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि गैर जनपद में पंजीकृत ई-रिक्शा का संचालन अब चंदौली जिले में नहीं होगा। ऐसे ई-रिक्शा जिले में चलते मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।

सड़क सुरक्षा पखवाड़े में महिला ई-रिक्शा चालकों का सम्मान



परिवहन विशेष न्यूज

बागपत जनपद में दो अक्टूबर से चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े का 16 अक्टूबर को समापन हो गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना था। इन कार्यक्रमों में स्कूल, कॉलेज, संस्थान, एवं ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

पखवाड़े के समापन समारोह में विशेष रूप से जिलाधिकारी जितेंद्र

प्रताप सिंह द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला ई-रिक्शा चालकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये महिला ई-रिक्शा चालक अपने साहसिक कदम से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस अवसर पर कहा कि "महिला ई-रिक्शा चालकों ने समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए स्वावलंबी बनने का साहसिक निर्णय लिया है, जो प्रेरणादायक है। इनके इस प्रयास को हम सभी को सराहना और समर्थन देना

चाहिए। समापन समारोह की रैली का समापन आरटीओ कार्यालय में हुआ, जहां सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेंद्र सिंह, संभागीय निरीक्षक विंध्याचल गुप्ता और समस्त परिवहन विभाग के स्टाफ ने उपस्थित चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। विशेष रूप से महिला ई-रिक्शा चालकों को सम्मानित किया गया, ताकि उनके इस साहसिक प्रयास को समाज में एक नई दिशा मिल सके।

बैटरी स्मार्ट ने पूरे किए भारत में 50 मिलियन बैटरी स्वैप

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क, बैटरी स्मार्ट ने अपने नेटवर्क पर 50 मिलियन बैटरी स्वैप पूरा होने की घोषणा की।

बैटरी स्मार्ट ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक भारत के 35 से ज्यादा शहरों में 1,400 से ज्यादा स्वैपिंग स्टेशनों तक अपने परिचालन का विस्तार किया है। कंपनी का नेटवर्क वर्तमान में लगभग 60,000 ड्राइवर्स को सहायता प्रदान करता है, जो बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल पेश करता है जिसका उद्देश्य ईवी अपनाने में आने वाली आम बाधाओं को दूर करना है।

बैटरी स्मार्ट के सह-संस्थापक और सीईओ पुलकित खुराना ने कहा, ₹50 मिलियन बैटरी स्वैप हासिल करना हमारे लिए सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है; यह ईवी अपनाने को सुलभ और किफायती बनाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे बैटरी-स्वैपिंग मॉडल की सफलता ईवी उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने की इसकी क्षमता में निहित है।

बैटरी-स्वैपिंग मॉडल से सवार लगभग दो मिनट में पूरी तरह चार्ज की गई बैटरी से बैटरी बदल सकते हैं, जिससे संभावित रूप से रेंज की चिंता कम हो सकती है और ईवी ऑपरेटरों



के लिए दक्षता में सुधार हो सकता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य बैटरी के मालिक होने की आवश्यकता को समाप्त करके ईवी चालकों के लिए अग्रिम लागत को कम करना भी है। बैटरी स्मार्ट की विस्तार रणनीति में मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए स्थानीय व्यवसायों के साथ साझेदारी करना शामिल है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां

चार्जिंग सुविधाएं सीमित हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ईवी पहुंच में वृद्धि होगी। यह विकास हाल ही में सरकार की पहल पीएम-इ-ड्राइव योजना से मेल खाता है, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। बिजली मंत्रालय ने हाल ही में बैटरी स्वैपिंग के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं,

जो देश में ईवी इकोसिस्टम के विकास को और बढ़ावा दे सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का एक विकल्प है जिसमें डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज की गई बैटरी से बदलना शामिल है। बैटरी स्वैपिंग का इस्तेमाल दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए किया जाता है जिनमें छोटी बैटरी होती है।

ब्लूस्मार्ट ने ड्राइवर पार्टनर्स के लिए नई टिपिंग सुविधा की शुरु

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राइड-हेलिंग सर्विस ब्लूस्मार्ट ने अपने ऐप पर टिपिंग फीचर शुरू किया है, जिससे राइडर्स अपने ड्राइवर पार्टनर को टिप दे सकते हैं। फेस्टिव कैम्पेन #RideToCelebrate के हिस्से के रूप में, ब्लूस्मार्ट राइडर्स द्वारा दी गई हर टिप को मैच करेगा, जिससे ड्राइवर के साप्ताहिक भुगतान में जमा की जाने वाली राशि प्रभावी रूप से दोगुनी हो जाएगी। जब ब्लूस्मार्ट उनकी टिप मैच करेगा, तो राइडर्स को सूचित किया जाएगा।

इस सुविधा का उद्देश्य सवारियों को अपने ड्राइवर्स के प्रति आभार प्रकट करने का एक आसान तरीका प्रदान करना है। ब्लूस्मार्ट फ्लीट के सह-संस्थापक और सीईओ अनिरुद्ध अरुण ने कहा, रहमारे ड्राइवर

पार्टनर इस अनुभव की रीह है... हमारे ग्राहकों द्वारा दिए गए सुझावों से मेल खाते हुए, हम आनंद को बढ़ा रहे हैं और हर यात्रा को #RideToCelebrate बना रहे हैं।

2019 में स्थापित, ब्लूस्मार्ट एक दक्षिण एशियाई इलेक्ट्रिक, फुल-स्टैक, वर्टिकल इंटीग्रेटेड ईवी राइड हेल्पिंग सर्विस और ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। ब्लूस्मार्ट दिल्ली एनसीआर और बैंगलूर में काम करता है और जून 2024 में यूएई में प्रीमियम ऑल-इलेक्ट्रिक लिमोसिन सेवा के रूप में लॉन्च होने के साथ ही इसने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कदम रखा। ब्लूस्मार्ट को यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अपने अग्रणी आवंटन प्रणाली के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया है।



बच्चों में स्क्रीन की लत को रोकने के लिए डिजिटल स्वच्छता गाइड



विजय गर्ग

माता-पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पास उपयोग की निगरानी करने के लिए कौशल और विशेषज्ञता की कमी है क्योंकि अक्सर सीमाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। अन्य मामलों में, माता-पिता के बीच आम सहमति की कमी है (यदि दोनों उपलब्ध हैं) कि सख्त माता-पिता कहानी के रखलनायक बनने के साथ उपयोग की निगरानी कैसे करें। सोशल मीडिया, या स्कूल अभिभावक व्हाट्सएप समूहों में, जिन छात्रों के माता-पिता बात करते हैं बच्चों को अक्सर स्कूल में अपने साथियों से तीखी प्रतिक्रिया का अनुभव होता है।

जब तकनीकी उपयोग की बात आती है तो स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए सीमाएँ निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यहाँ एक विशेषज्ञ मार्गदर्शिका है जो आपको बताती है कि कैसे मादक द्रव्यों की लत को तरह, स्क्रीन की लत भी डोपामाइन के स्तर में वृद्धि पैदा करने के लिए जानी जाती है। जितना अधिक स्क्रीन समय होगा, बच्चे के डिजिटल डिवाइस से जुड़ने का जोखिम उतना अधिक होगा मादक द्रव्यों की लत की तरह, स्क्रीन की लत भी डोपामाइन के स्तर में वृद्धि पैदा करने के लिए जानी जाती है। जितना अधिक स्क्रीन समय होगा, बच्चे के डिजिटल डिवाइस से जुड़ने का जोखिम उतना अधिक होगा छोटे काम में स्क्रीन की लत एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। अमेरिका में, स्कूलों की बढ़ती संख्या मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं तो प्रतिबंधित कर रही है। यह लेख इस बात पर क़रीब से नज़र डालता है कि बच्चों में स्क्रीन की लत का कारण क्या है और स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता इस आदत को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले, मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूँ: 'रिया एक उत्साही छात्र था जिसने अपना होमवर्क तुरंत पूरा करने में मज़ा आता था। लेकिन हाल ही में उनके ग्रेड में गिरावट आनी शुरू हो गई है। उनकी पढ़ाई में लगाया गया समय और प्रयास अब डिजिटल उपकरणों पर खर्च हो रहा है। स्कूल जाने में रुचि कम हो गई है, बाहर खेलने में अरुचि हो गई है और छुट्टी के दिनों में वह अपना अधिकांश समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है, कभी-कभी रात में भी। परिणामस्वरूप, उसे स्कूल के लिए समय पर उठने में कठिनाई होती है, जिससे दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन रहता है। जब उससे स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय के बारे में पूछा जाता है तो वह रक्षात्मक और उतेजित हो जाता है। 'संचार टूटने से घर में तनाव बढ़ गया है, रिया को गलत समझा जा रहा है और उसके माता-पिता निराश हैं।' नशे की लत वाले पदार्थ मस्तिष्क में एक बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। दुर्घयोग्य की दवाएँ - जैसे ओपियोइड, कोकीन, यानिकोटिन - डोपामाइन को इनाम मार्ग में बाढ़ का कारण बनती हैं, जो प्राकृतिक इनाम (व्यायाम, पढ़ना, चॉकलेट) से कई गुना अधिक है। मस्तिष्क इस उछाल को याद रखता है और इसे नशेरी पदार्थ के साथ जोड़ता है और एक इनाम मार्ग स्थापित करता है, एक दुष्चक्र बनाता है, और उपयोगकर्ता को बार-बार पदार्थ का सेवन करने



के लिए प्रोत्साहित करता है। स्क्रीन व्यसन में पदार्थों के समान ही तंत्र होता है, जो डोपामाइन में समान वृद्धि पैदा करता है। स्क्रीन के उपयोग में निरंतर वृद्धि के साथ, मस्तिष्क के सर्किट अनुकूल हो जाते हैं और डोपामाइन के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। नतीजतन, आप जो देखते हैं वह समान आनंद का अनुभव करने के लिए अधिक उपयोग करने की बढ़ती आवश्यकता है। एक आम गलतफ़हमी यह है कि लत एक पसंद या नैतिक समस्या है। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता। एक निश्चित बिंदु के बाद, लत शारीरिक और भावनात्मक भलाई पर प्रभाव डालने वाली एक जैविक समस्या बन जाती है। माता-पिता को हस्तक्षेप करने, सही व्यवहार अपनाने और अपने बच्चों को जीवन कौशल के रूप में स्क्रीन प्रबंधन सिखाने की स्पष्ट आवश्यकता है। सीमाएँ निर्धारित करने में कठिनाई छोटे बच्चों के माता-पिता अक्सर सीमाएँ निर्धारित करने में संघर्ष करते हैं। यह कई कारणों पर आधारित है, जिनमें उपयोग की निगरानी में लगने वाला समय, घर पर बच्चे के साथ संघर्ष, या सामाजिक मानदंड जहाँ अन्य बच्चों के पास उपकरणों तक पहुंच है।

माता-पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पास उपयोग की निगरानी करने के लिए कौशल और विशेषज्ञता की कमी है क्योंकि अक्सर सीमाओं को

दरकिनार कर दिया जाता है। अन्य मामलों में, माता-पिता के बीच आम सहमति की कमी है (यदि दोनों उपलब्ध हैं) कि सख्त माता-पिता कहानी के रखलनायक बनने के साथ उपयोग की निगरानी कैसे करें। सोशल मीडिया, या स्कूल अभिभावक व्हाट्सएप समूहों में, जिन छात्रों के माता-पिता बात करते हैं बच्चों को अक्सर स्कूल में अपने साथियों से तीखी प्रतिक्रिया का अनुभव होता है। सख्त सीमाएँ कैसे निर्धारित करें? स्वस्थ स्क्रीन समय के लिए हालाँकि सीमाएँ निर्धारित करने में अंतर्निहित कठिनाइयों हो सकती हैं, यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन्हें आप उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठा सकते हैं: स्वच्छता बनाए रखना: सुनिश्चित करें कि आपके घर के सभी उपकरण पहचाने गए हैं और पासवर्ड से सुरक्षित हैं। अक्सर, पुराने उपकरणों का उपयोग छोटे बच्चों द्वारा किया जाता पाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए माता-पिता के नियंत्रण को रचालू करने की आवश्यकता है। हालाँकि यह उन बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण लग सकता है जिनके पास फोन हैं, लेकिन अपने बच्चे से अपने फोन के पासवर्ड साझा करने के लिए कहना असंभव नहीं है। ध्यान दें: यह गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है, यह उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए डेस्कटॉप बनाम लैपटॉप के उपयोग को प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत

उपकरणों के बजाय टीवी पर सामग्री देखा हानिकारक सामग्री के उपभोग में स्वचालित बाधाएँ पैदा करता है। संतुलन स्थापित करना: जबकि आपका बच्चा स्क्रीन का उपयोग कर रहा होगा, यह ज़ांचना महत्वपूर्ण है कि क्या उनके जीवन के अन्य पहलू जैसे खेल खेलना, उनकी दोस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौद, भूख और आत्मसम्मान अप्रभावित हैं। उचित सीमाएँ निर्धारित करना: डिजिटल पहुंच से पूरी तरह इनकार करने से बचें; इसके बजाय, पुरस्कारों के साथ सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करें। सहमत सीमाओं की अवहेलना के परिणामों को लागू करें, जैसे नियमों को तोड़ने के लिए स्क्रीन का समय कम करना। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना: बच्चे अपने व्यवहार को आदर्श बनाने के लिए अपने माता-पिता की ओर देखते हैं। माता-पिता के रूप में आप जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। स्वस्थ डिजिटल आदतों का अनुकरण करना, अपने स्वयं के संघर्षों और प्रबंधन तकनीकों को डिजिटल तकनीक के साथ उचित रूप से साझा करना आपके बच्चे को अपनी कठिनाइयों के बारे में बोलने और आपके उदाहरण का अनुसरण करने की अनुमति दे सकता है। पथ पर बने रहना: प्राथमिक प्रतिरोध की अपेक्षा करें। आपका बच्चा शुरुआत में अधिक नखरे दिखा सकता है या अधिक तीव्रता से

स्क्रीन टाइम की मांग कर सकता है, इससे पहले कि उसका व्यवहार अंततः कम हो जाए। इसे सुदृढ़ीकरण (असीमित स्क्रीन समय) रोके जाने के जवाब में रविलुप्त होने वाला विस्फोटक कहा जाता है। अनुपालन के लिए शुरुआत में अच्छी तरह से पुरस्कृत करना महत्वपूर्ण है। पेशेवर मदद लेना: रिया के मामले की तरह, यदि आप अपने बच्चे के ग्रेड में चिंताजनक गिरावट, लगातार स्कूल जाने से इंचार या सीमाएँ निर्धारित करते समय माता-पिता-बच्चे के रिश्तों में टकराव देखते हैं, तो पेशेवर मदद लेना बुद्धिमानी होगी। बच्चों से लेकर किशोरों तक के माता-पिता के लिए एक डिजिटल स्वच्छता मार्गदर्शिका यदि आपका बच्चा 0-6 वर्ष के युवा का है: न्यूनतम स्क्रीन समय निर्धारित करें। माता-पिता को सहभागिता के बिना हैडहेल्ड उपकरणों तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं होनी चाहिए। इसमें सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान या किसी रेस्तरां में अपने बच्चे को फोन देना शामिल है। अपने बच्चे से उस सामग्री के बारे में बात करें और उत्सुक रहें जो वे देख रहे हैं। इससे संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। यदि आपका बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच है: स्क्रीन टाइम के आसपास नियम और कानून बनाएं। वे क्या सामग्री देख रहे हैं, खोज रहे हैं और सुन रहे हैं, इस पर कड़ी नज़र रखें। सुनिश्चित करें कि वे आपकी निगरानी के बिना ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकें। 13-18 वर्ष के बच्चों के लिए: बड़े किशोरों को अपना स्क्रीन टाइम डेटा साझा करने के लिए आमंत्रित करें। चर्चा करें कि स्क्रीन टाइम आपकी उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। उन्हें अपने कमा का दरवाजा जितना संभव हो उतना खुला रखने के लिए प्रोत्साहित करें लेकिन कमरे में बार-बार प्रवेश न करें। स्क्रीन की लत एक वास्तविक समस्या है जो महामारी के कारण वयस्कों और बच्चों दोनों को समान रूप से प्रभावित कर रही है। माता-पिता को अपने बच्चे के स्क्रीन उपभोग पैटर्न के प्रति सतर्क, सक्रिय और व्यवस्थित रहने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म तलाशने और अपने बच्चे की दुनिया के बारे में जानकारी रखने से आपको अपनी आशंकाओं के बारे में उनसे बात करने के लिए बेहतर भाषा मिल सकती है। सीमाएँ निर्धारित करना अलावा विधि में कठिन लग सकता है लेकिन अंततः ई लंबी अवधि में भारी लाभकारी होगा।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्टूट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

स्कूल काउंसलिंग (परामर्श) की आवश्यकता और दायरा

विजय गर्ग

दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, जीवनशैली बदल रही है, बच्चों के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो गई है। बच्चों को स्कूल, परिवार, समाज, दोस्तों आदि से बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धात्मकता, पारिवारिक समस्याएँ, पारिवारिक दबाव, बदमाशी, भाई-बहन की प्रतिद्वंद्विता, भय, दुर्व्यवहार, कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका छात्रों को सामना करना पड़ता है। घरों की तरह, स्कूलों को भी बच्चों के पोषण, समग्र विकास और शैक्षिक विकास के लिए एक प्रमुख कारक माना जाता है। स्कूल बच्चों के लिए दूसरे घर के रूप में काम करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे के समग्र विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखा जाए। स्कूल क्या है? स्कूल बच्चों को शिक्षा देने वाली एक संस्था है। परिवारों की तरह मानव समाज के पुनरुत्पादन और उन्हें नवप्रवर्तन और परिवर्तन के लिए सक्षम परिस्थितियाँ प्रदान करने में उनकी अद्वितीय भूमिका है। स्कूल बच्चों को विविध अनुभव प्रदान कर सकते हैं, जो उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए ढाल सकते हैं। स्कूल में गतिविधियाँ स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। एक स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। इसे मानव ज्ञान द्वारा सदियों से एकत्र की गई जानकारी को व्यापक और व्यवस्थित तरीके से प्रसारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूलों के बिना यह सुनिश्चित करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर होता कि युवा पीढ़ी को अपने आसपास की दुनिया की सभी आवश्यक समझ हो। स्कूल बच्चों को समस्या समाधान कौशल, पारस्परिक और अंतर-व्यक्तिगत कौशल आदि जैसे महत्वपूर्ण कौशलों में प्रशिक्षित करते हैं। आवश्यक कौशल जो बच्चों को दिन-प्रतिदिन की वस्तुओं के साथ बातचीत करने और समझने में मदद करते हैं, उन्हें स्कूलों में विकसित किया जाता है। इसके अलावा, स्कूल बच्चे के भविष्य के करियर की नींव भी रखते हैं। हालाँकि स्कूल में विद्यार्थियों के समय का बड़ा हिस्सा शिक्षाविदों पर खर्च होता है, खेल, ललित कला आदि जैसी सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती हैं। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा तलाशने और अपनी ताकत निखारने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, खेल से बच्चे में पारस्परिक कौशल, नेतृत्व गुण और कल्याण का निर्माण होता है। स्कूल में बातचीत स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आते हैं। समाज के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न व्यक्ति एक साथ आते हैं। वे एक साझा मंच और एक साझा उद्देश्य साझा करते हैं। अक्सर, एक बच्चे की अपने परिवार के अलावा पहली बातचीत उस स्कूल से होती है जिसमें वह पढ़ता है। बच्चे की प्राथमिक बातचीत स्कूल के अन्य बच्चों और उसके शिक्षकों के साथ होगी। इस उद्देश्य से, साथी छात्रों के साथ बातचीत बच्चे के समग्र विकास पर बहुत प्रभाव डालती है क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। स्कूल में बच्चों के विकास में शिक्षकों का व्यक्तिगत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहायक कर्मचारी भी छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, उदाहरण के लिए सहायक, कार्यालय कर्मचारी आदि। स्कूल में प्रत्येक छात्र के लिए एक नियंत्रित और तनाव मुक्त वातावरण होना बहुत महत्वपूर्ण है जब उसे इस तरह की बातचीत से गुजरना पड़ता है। स्कूल परामर्श स्कूल मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य छात्रों के सीखने को बढ़ाना और बढ़ावा देना

है। ये सेवाएँ सभी स्तरों पर छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनका उद्देश्य स्कूलों और स्कूलों में छात्रों के शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक और करियर विकास को सुविधाजनक बनाना है समुदाय। एक पेशे के रूप में परामर्श निश्चित रूप से पश्चिमी देशों की देन है। भारतीय समाज अपने मजबूत पारिवारिक संबंधों और गर्मजोशी भरी सामुदायिक भावना और आध्यात्मिक सार के साथ संस्कृत के समय में विभिन्न मनोसामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए सदमे अवशोषक और सहायता प्रणाली प्रदान करता रहा है। शायद, यह लगातार भारत में परामर्श के पेशे की कम वृद्धि का कारण बनता है। हाल के वर्षों में ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की बढ़ती स्थिति के साथ पूरी तरह से कायापलट हो गया है, संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना, स्कूलों में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, बच्चों की समाजक्षमता में वृद्धि, अत्यधिक तकनीकी प्रगति, साधियों और माता-पिता के दबाव के परिणामस्वरूप एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत अधिक तनाव है। children.स्कूल परामर्शदाता बढ़ते तनाव और दबाव से निपटने और युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान देने के लिए छात्रों और अभिभावकों के लिए एक आशीर्वाद की तरह प्रतीत होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल मार्गदर्शन और परामर्श का क्षेत्र बदल गया है। भारत में स्कूल परामर्श एक अपेक्षाकृत युवा पेशा है। यहां भारत में स्कूल काउंसलिंग के इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया गया है। 1954 में, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की। इसने वर्तमान परामर्श के बीज बोये। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद स्कूलों में मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू हुए। 1966 में इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 3000 विद्यालय किसी न किसी रूप में परामर्श सेवाएँ प्रदान कर रहे थे। वर्ष 2000 से, केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो ने मार्गदर्शन पेशेवरी के प्रशिक्षण का काम अंजमिर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में क्षेत्रीय मार्गदर्शन संस्थानों को सौंप दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त पाठ्यक्रम और करियर विकल्पों में मदद करना है। इक्कीसवीं सदी में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का विलय हो गया है। मार्गदर्शन सेवाओं की सूचना देने की क्षमता को सभी ग्रेड स्तरों पर परामर्श से विक्रेण द्वारा पेश किए गए व्यक्तिगत विकास के अवसरों के साथ समेटित किया गया है। यह छात्रों के सीखने, निर्णय लेने और आत्म-जागरूकता को बढ़ाने और विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए किया गया है। नियमित पाठ्यक्रम प्रोग्रामिंग में सेवा वितरण के मार्गदर्शन घटक को शामिल करना अधिक आम हो गया है। आजकल, स्कूल परामर्शदाताओं को स्कूल स्टाफ के अतिरिक्त परामर्शदाताओं के लिए स्थायी स्टाफ पदों का चयन कर रहे हैं, जहाँ पहले यह केवल अस्थायी था। छात्रों के साथ-साथ माता-पिता भी ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं और उन स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें पैलन पर पूर्णकालिक परामर्शदाता होते हैं। परामर्श के उद्देश्य परामर्श के उद्देश्य स्पष्ट और उपयुक्त तथा स्थिति के अनुरूप होने चाहिए। परामर्श दक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब परामर्श सत्र का लक्ष्य स्पष्ट, उचित



और स्पष्ट होना हो। छात्र परामर्श न केवल छात्रों को बल्कि माता-पिता और शिक्षकों को भी सहायता प्रदान करता है। स्व-शिक्षा को हर बच्चे के दिमाग में डाला जाना चाहिए। स्व-शिक्षा छात्रों को अधिक स्वतंत्र बनाती है। स्कूल परामर्श सेवा का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों में स्व-शिक्षा को बढ़ाना और बढ़ावा देना और उन्हें स्वतंत्र बनने में मदद करना है। छात्र परामर्शदाता एक उद्देश्य न केवल स्व-शिक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि योजना, परामर्श, रोकथाम, शिक्षा जैसे मुख्य कार्यों को भी बढ़ावा देना है। एन आर् डि छात्र परामर्श का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना और जानकारी के लिए आवश्यक सुझाव देना है। स्कूल परामर्शदाताओं की एक पेशेवर जिम्मेदारी है कि वे छात्र के सामने आने वाली समस्या का पता लगाएँ और छात्र और उसके परिवेश पर इसके प्रभाव का पता लगाएँ। स्कूल परामर्श से छात्रों को समस्य के कारणों की पहचान करने और विश्वासों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। स्कूल परामर्श से छात्रों को उनकी गंभीरता के अनुसार समस्याओं की पहचान करने और तदनुसार उचित चिंताओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलनी चाहिए। छात्रों को परामर्श के प्रभाव को समझने और उन्हें उनकी क्षमताओं का एहसास करने में मदद करने के लिए सत्र के अंत में मूल्यांकन, सारांश की योजना बनाई जानी चाहिए। स्कूल परामर्श की आवश्यकता शैक्षणिक संबंधी एक स्कूल में, छात्र अलग-अलग तरीकों से सिंभन होते हैं। उनकी क्षमताएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। अक्सर शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर उसकी क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिगत ध्यान देने में सक्षम नहीं होता है। इस प्रकार, कम शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है। एक बच्चे की पढ़ाई कई कारकों से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, व्यवहार संबंधी मुद्दे: जहाँ बच्चे का व्यवहार सीधे उसके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यहाँ, परामर्श से बच्चे में व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण की पहचान करने और उसे ठीक करने में मदद मिलती है। परामर्श व्यवहार संबंधी समस्याओं के मूल कारण का पता लगाने में भी मदद करता है। न्यूरोलॉजिकल मुद्दे: एक बच्चा डिस्लेक्सिया आदि जैसी सीखने की क्षमताओं से पीड़ित हो सकता है। ये स्थितियाँ अप्रशिक्षित लोगों के लिए बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं और इनका पता नहीं चल पाता है। ऐसी स्थितियों को गलत तरीके से व्यवहारिक माना जा सकता है जिससे बच्चे को बहुत अधिक तनाव हो सकता है। एक परामर्शदाता इन स्थितियों की पहचान करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है और आवश्यकतानुसार आवश्यक सहायता प्रदान करता है। शारीरिक विकलांगता: शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को अधिक मात्रा में परामर्श की आवश्यकता होती है। उनमें आत्म-सम्मान कम होने की संभावना अधिक होती है और उन्हें अधिक

सहायता की आवश्यकता होती है। उन्हें रोजमर्रा की बुनियादी गतिविधियों में भी मदद की आवश्यकता होगी। परिवार से संबंधित: एक बच्चे का परिवार उसे व्यवहार को ढालने में एक बड़ी भूमिका निभाता है जिसका स्कूल में उसके आचरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। घर की समस्याएँ बच्चे पर तनाव डालती हैं और इसका सीधा असर उसके शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, माता-पिता तलाक से गुजर रहे हैं, बच्चे को घर पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी नकारात्मक घटनाएँ बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। एक परामर्शदाता ऐसे मुद्दों की पहचान करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद कर सकता है। छात्र की दूसरों के साथ बातचीत भी काफी हद तक उसके घर की स्थितियों से प्रभावित होती है। यह महत्वपूर्ण है कि घर में अनुकूल माहौल बना रहे जिससे बच्चे के पालन-पोषण में मदद मिलेगी। मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान: तनाव, अकेलापन, धमकाना, रैगिंग, सहकर्मी समायोजन, माता-पिता और शिक्षक का दबाव छात्रों की कुछ संभावित मनोसामाजिक समस्याएँ हैं जिनका समाधान स्कूल परामर्शदाता द्वारा किया जा सकता है। चरम मामलों में, परामर्शदाता छात्रों को मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सा या अन्य विशिष्ट कर्मियों के पास भेज सकता है। माता-पिता के लिए परामर्श: एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन यह है कि माता-पिता को भी परामर्श देने की आवश्यकता है। छात्र परामर्शदाता निम्नलिखित मुद्दों पर माता-पिता को परामर्श प्रदान कर सकता है: i. बच्चे को उसकी शक्तियों और कमजोरियों के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। द्वितीय, शैक्षिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बच्चे पर अनुचित दबाव और तनाव का दुष्प्रभाव iii. बच्चे की रुचियों और योग्यता और उसकी उपयुक्तता और करियर का चुनाव। iv. बच्चे की सीखने की अक्षमता, यदि कोई हो और मुकाबला करने की रणनीतियाँ। v. बच्चे की मनोसामाजिक समस्याएँ, यदि कोई हो और मुकाबला करने की रणनीतियाँ। vi. परामर्श से जुड़े कलंक के लिए परामर्श। शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए परामर्श: विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले और अद्वितीय व्यक्ति रखने वाले छात्रों की बड़ी संख्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को भी परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्शदाता को निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए: i. शारीरिक दंड की निरर्थकता की समझ। ii. सिखाने वाले बच्चे को समझना अद्वितीय है और प्रत्येक छात्र को वेसे ही स्वीकार करना जैसे वह है। iii. छात्रों की सीखने की अक्षमताओं की पहचान करना। iv. बच्चे की मनोसामाजिक/समायोजन समस्याओं की पहचान करना। v. प्रत्येक छात्र से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के तरीके। vi. छात्रों का समग्र

विकास स्कूल परामर्श का दायरा 1. परामर्श स्कूल परामर्श कार्यों में हस्तक्षेप और रोकथाम सेवा दोनों प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, समूह और कक्षा कार्य शामिल हो सकते हैं। परामर्श सेवा का उद्देश्य है भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, करियर, शारीरिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का विकासात्मक रूप से उचित विकास को बढ़ावा देना छात्रों को उनके परिवारों और उनके समुदाय के माध्यम से, आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे क्षेत्रों में और निर्णय लेने और सामाजिक संबंधों जैसे कौशल में बढ़ने में मदद करें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से एक छात्र की शैक्षणिक प्रगति का समर्थन करना और उसे बढ़ाना, जिसमें व्यक्तिगत मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, अध्ययन की आदतों और संगठनात्मक कौशल में निर्देश, और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं (आईईपी) के विकास में सहायता करना शामिल हो सकता है, जिसमें व्यवहार हस्तक्षेप योजनाएँ (बीआईपी) शामिल हैं।) और व्यक्तिगत संक्रमण योजनाएँ (आईटीपी)। 2. रोकथाम स्कूल परामर्शदाता तीन तरीकों से छात्रों की सफलता को सुविधाजनक बनाने के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित कर सकते हैं: स्कूल टीम प्रक्रिया के भाग के रूप में छात्र सहायता टीम प्रक्रिया के भाग के रूप में एक व्यक्तिगत परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राथमिक रोकथाम स्तर किसी समस्या को उत्पन्न होने से रोकने पर केंद्रित है। विद्यालय में सकारात्मक माहौल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एक सुरक्षित स्कूल वातावरण की सुविधा के लिए एक स्कूल कार्यक्रम एक उदाहरण हो सकता है। रोकथाम का द्वितीय स्तर समस्याओं के शुरुआती संकेतों पर केंद्रित है। लक्ष्य अवधि को कम करने या किसी समस्या के प्रभाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना है। उदाहरणों में स्नातक न कर पाने और रोकथाम की रणनीतियों को विकसित, कार्यान्वित और मूल्यांकन किया जा सके। उदाहरणों में स्कूल से निलंबन का सामना कर रहे छात्र के लिए संक्रमणकालीन परामर्श और योजना पुनः एकीकरण, आत्महत्या करने वाले छात्र को स्थिर करना और विस्फोटक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छात्र को तनावमुक्त करना शामिल हो सकता है। रोकथाम और निवारक योजना का पूरा क्षेत्र जटिलता या गंभीरता की एक श्रृंखला पर प्रतिक्रिया करता है। इस योजना में अक्सर दूसरों के साथ परामर्श करना और स्कूल प्रभाग के चिकित्सकों या बाहरी एजेंसियों को रेफर करना शामिल होता है। काउंसलिंग के अलावाजी कौशल, रोकथाम योजना में सहायता करने वाले सहायक विशेष कौशल सेट शामिल हो सकते हैं। स्कूल परामर्शदाताओं की गतिविधियों के दायरे की व्यावसायिक सीमाओं को पहचानने में दूसरों की मदद करना दूसरों को अपनी समस्याएँ सुलझाने

और सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करना परामर्श प्रक्रिया के लिए विशेष ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, समूह और कक्षा कार्य शामिल हो सकते हैं। परामर्श सेवा का उद्देश्य है भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, करियर, शारीरिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का विकासात्मक रूप से उचित विकास को बढ़ावा देना छात्रों को उनके परिवारों और उनके समुदाय के माध्यम से, आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे क्षेत्रों में और निर्णय लेने और सामाजिक संबंधों जैसे कौशल में बढ़ने में मदद करें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से एक छात्र की शैक्षणिक प्रगति का समर्थन करना और उसे बढ़ाना, जिसमें व्यक्तिगत मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, अध्ययन की आदतों और संगठनात्मक कौशल में निर्देश, और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं (आईईपी) के विकास में सहायता करना शामिल हो सकता है, जिसमें व्यवहार हस्तक्षेप योजनाएँ (बीआईपी) शामिल हैं।) और व्यक्तिगत संक्रमण योजनाएँ (आईटीपी)। 2. रोकथाम स्कूल परामर्शदाता तीन तरीकों से छात्रों की सफलता को सुविधाजनक बनाने के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित कर सकते हैं: स्कूल टीम प्रक्रिया के भाग के रूप में छात्र सहायता टीम प्रक्रिया के भाग के रूप में एक व्यक्तिगत परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राथमिक रोकथाम स्तर किसी समस्या को उत्पन्न होने से रोकने पर केंद्रित है। विद्यालय में सकारात्मक माहौल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एक सुरक्षित स्कूल वातावरण की सुविधा के लिए एक स्कूल कार्यक्रम एक उदाहरण हो सकता है। रोकथाम का द्वितीय स्तर समस्याओं के शुरुआती संकेतों पर केंद्रित है। लक्ष्य अवधि को कम करने या किसी समस्या के प्रभाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना है। उदाहरणों में स्नातक न कर पाने और रोकथाम की रणनीतियों को विकसित, कार्यान्वित और मूल्यांकन किया जा सके। उदाहरणों में स्कूल से निलंबन का सामना कर रहे छात्र के लिए संक्रमणकालीन परामर्श और योजना पुनः एकीकरण, आत्महत्या करने वाले छात्र को स्थिर करना और विस्फोटक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छात्र को तनावमुक्त करना शामिल हो सकता है। रोकथाम और निवारक योजना का पूरा क्षेत्र जटिलता या गंभीरता की एक श्रृंखला पर प्रतिक्रिया करता है। इस योजना में अक्सर दूसरों के साथ परामर्श करना और स्कूल प्रभाग के चिकित्सकों या बाहरी एजेंसियों को रेफर करना शामिल होता है। काउंसलिंग के अलावाजी कौशल, रोकथाम योजना में सहायता करने वाले सहायक विशेष कौशल सेट शामिल हो सकते हैं। स्कूल परामर्शदाताओं की गतिविधियों के दायरे की व्यावसायिक सीमाओं को पहचानने में दूसरों की मदद करना दूसरों को अपनी समस्याएँ सुलझाने

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्टूट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

जीरो हो गई कंपनी की वैल्यू, फाउंडर रवींद्र ने निवेशकों को ढहराया जिम्मेदार

परिवहन विशेष न्यूज

एक समय एडटेक कंपनियों के टॉप में Byju का नाम था पर अब कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई। कंपनी के इस हालत को लेकर बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्र (Byju Raveendran) ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी के जीरो वैल्यू होने के जिम्मेदार निवेशक हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। एजुकेशन और टेक्नॉलजी कंपनी यानी एडटेक सेक्टर में एक समय बायजू (Byju's) का जलवा रहा है। यह इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रह चुकी है, पर अब इसकी स्थिति एकदम उलट हो गई है। जी हां, कुछ समय से बायजू वित्तीय संकट से घिरी हुई है।

निवेशक हैं जिम्मेदार
कंपनी के वित्तीय संकट को लेकर



बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्र (Byju Raveendran) ने कहा कि अब इसकी वैल्यू जीरो हो गई है। कंपनी की इस हालत के लिए उन्होंने निवेशकों को जिम्मेदार ढहराया है। उन्होंने कहा कि जब मैं कंपनी को एक्सपेंड और टेकओवर करने की कोशिश कर रहा था तब निवेशकों ने मेरा साथ दिया। लेकिन जैसे ही कंपनी पर संकट के बादल छाए वैसे ही सभी निवेशक पीछे हट खड़े हुए।

हालांकि, कंपनी के फाउंडर ने भरोसा जताया है कि कंपनी जल्द ही संकट की स्थिति से बाहर आने में कामयाब होगी। बता दें कि जब से बायजू संकट में आया है तब से यह पहली बार है जब कंपनी के फाउंडर सामने आए। जी हां, बायजू रवींद्र दुबई के घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह सभी बयान दिये हैं।
मैनेजमेंट बदलने की हो रही थी

मांग
बायजू रवींद्र ने कहा कि निवेशक बिना कोई प्लान के मैनेजमेंट बदलने की मांग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 के बाद से कंपनी में केवल हम लोगों ने ही निवेश किया है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि Prosus समेत कई निवेशकों ने पिछले 4 से 5 सालों में कोई निवेश नहीं किया है।

Prosus जैसे निवेशकों ने एक समय के बाद कंपनी में अपने निवेश को राइट ऑफ कर दिया। बता दें कि संकट से पहले बायजू देश की सबसे बड़ी वैल्यू कमांड करने वाली स्टार्टअप कंपनी थी। कंपनी पर जैसे ही संकट के बादल मंडराए उसके तुरंत बाद कंपनी के तीन डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद कंपनी को फंड जुटाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा।

RBI गवर्नर ने कह दी बड़ी बात, बोले- हम पुलिस नहीं बल्कि वित्तीय बाजार पर रखते हैं निगरानी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्लूमबर्ग की मेजबानी में आयोजित इंडिया क्रेडिट फोरम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरबीआई पुलिस की तरह काम नहीं करता है। आरबीआई केवल वित्तीय बाजार पर निगरानी रखता है और आवश्यक होने पर वह कार्रवाई करता है। इसके अलावा शक्तिकांत दास ने महंगाई दर और भारत के विकास पर भी टिप्पणी दी।

नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन एनबीएफसी और सचिन बंसल की नवी फिनसर्व पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर आज केंद्र बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Gov Shaktikanta Das) ने कहा कि आरबीआई पुलिस कर्मी के तौर पर काम नहीं करता है। आरबीआई केवल फाइनेंशियल मार्केट पर निगरानी रखता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करता है।
बता दें कि गुरुवार को आरबीआई ने सचिन बंसल की नवी फिनसर्व और तीन अन्य एनबीएफसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आरबीआई के निर्देश के अनुसार अब यह वित्तीय संस्थान 21 अक्टूबर



2024 के बाद से कोई लोन को स्वीकृति और वितरण नहीं कर पाएंगे।

ब्लूमबर्ग की मेजबानी में आयोजित इंडिया क्रेडिट फोरम में शक्तिकांत दास ने कहा कि हम पुलिस कर्मी नहीं हैं बल्कि हम वित्तीय बाजार को बहुत करीब से देखते हैं। हमें जब भी आवश्यक लगता है तो हम कार्रवाई भी करते हैं।

सीमा के भीतर है महंगाई
भारत में मौजूद महंगाई दर को लेकर शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी भी देश की महंगाई लक्ष्य सीमा के भीतर है। आने वाले समय में महंगाई के कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत के विकास पर उन्होंने कहा कि भारत के विकास की कहानी बरकरार है। ऐसे में आरबीआई भारत के विकास और महंगाई को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की निगरानी में बहुत सावधान है।

एक्सिस बैंक के शेयरों में शानदार तेजी, तिमाही नतीजे के बाद 5 फीसदी चढ़ा स्टॉक

प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक ने दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है। आज एक्सिस बैंक के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। बैंक ने अपने तिमाही नतीजों में नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम की जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव वाले कारोबार के बीच प्राइवेट सेक्टर का बैंक एक्सिस बैंक (Axis Bank) के शेयर में तेजी आई। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद बैंक के शेयर चढ़ गए। बैंक ने गुरुवार को सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान किया था।

एक्सिस बैंक के शेयरों का हाल
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर एक्सिस बैंक के शेयर 4.11 फीसदी चढ़कर 1,178.75 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयर 4.13 फीसदी की बढ़त के साथ 1,178.70 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। खबर लिखते वक्त एक्सिस बैंक के शेयर (Axis Bank Share Price) 63.10 फीसदी चढ़कर 1,194.95 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसी है बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मंस
एक्सिस बैंक ने तिमाही नतीजों (Axis Bank Q2 Result) में बताया कि बैंक का कंसॉलिडेट नेट प्रॉफिट 19.29 फीसदी बढ़कर 7,401.26 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, बैंक की नेट इंटरैस्ट इनकम भी 9 फीसदी बढ़कर 13,483 करोड़ रुपये हो गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 19 फीसदी बढ़कर 6,917.57 करोड़ रुपये हो गई। इस तिमाही में हमने डिजिटल कौशल और एडवांसमेंट को संतुलित करते हुए अपनी शाखाओं का भी विस्तार किया और हमने अपने ग्राहकों के और निकट पहुंचने का भी पूरा प्रयास किया है। हमने पिछले तीन



महीनों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 150 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक ने कोलकाता में एक नए कॉर्पोरेट कार्यालय की नींव रखकर अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को मजबूत किया। यह नया कॉर्पोरेट कार्यालय पूर्वी क्षेत्र में सभी गतिविधियों का केंद्र होगा। हमने अपने निजी बैंकिंग व्यवसाय 'बरगंडी प्राइवेट' नेटवर्क का विस्तार 15 नए शहरों तक किया है, जिससे देशभर में इसकी उपस्थिति 42 स्थानों तक बढ़ गई है। इस तरह हम देश के तेजी से विकसित हो रहे टैटुर 2 बाजारों में विशिष्ट धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी
बैंक का नेट इंटरैस्ट मार्जिन 0.12 फीसदी से बढ़कर 3.99 फीसदी हो गया। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में बैंक का टोटल इनकम 37,142 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान तिमाही में 31,660 करोड़ रुपये था। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार बैंक ने टोटल डिपॉजिट फ्रंट पर 14 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की।

फेस्टिव सीजन के शुरुआत में ही सोने ने दिखाया तेवर, 80000 रुपये के करीब पहुंचा इस शहर में गोल्ड प्राइस

फेस्टिवल सीजन में सोने-चांदी के दामों में अक्सर तेजी देखने को मिलती है। डिमांड के बढ़ जाने और वैश्विक स्तर पर हो रहे भू-राजनीतिक घटना की वजह से इनके दाम में तेजी आती है। भारत के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम अपडेट हो गए हैं। नए अपडेट के अनुसार इन दोनों कीमती धातुओं के दामों में तेजी आई है।

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में फेस्टिवल के शुरुआत के साथ ही गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। गोल्ड की डिमांड बढ़ने और भू-राजनीतिक गतिविधियों की वजह से गोल्ड की कीमतों में भी तेजी आई है। आज भी सोने और चांदी के दाम में इजाफा हुआ है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम जारी कर दिये हैं।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों की खरीदारी बढ़ने से घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की मांग रिकॉर्ड स्तर पर मजबूत हो गई है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के कारण अनिश्चितता के बीच निवेशक पीली धातु को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं।

व्या है गोल्ड की कीमत
ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार फेस्टिवल सीजन की मजबूत मांग के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सोना 550 रुपये बढ़कर 79,900 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 24 कैरेट वाले गोल्ड की कीमत गुरुवार को 79,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

सोने की कीमतों में पिछले तीन दिनों से तेजी जारी है। इन तीन दिनों में सोना के दाम 550 रुपये उछल गए हैं। पिछले सत्र में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 78,950 रुपये प्रति



10 ग्राम थी।
वायदा कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 77,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। दिन के दौरान सोना वायदा 77,667 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

कितनी महंगी हुई चांदी
चांदी के दाम में भी आज तेजी देखने को मिली है। आज सिल्वर 1,000 रुपये उछलकर 94,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बीते दिन गुरुवार को चांदी

93,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।
एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 1,231 रुपये या 1.34 प्रतिशत उछलकर 92,975 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

सोने की कीमतें कॉमेक्स के साथ-साथ घरेलू मोर्चे पर भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं, जो सुरक्षित-हेवन मांग से लाभान्वित हुईं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में करीबी मुकाबले के कुछ ही हफ्ते बचे हैं। जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दर

में कटौती से भी मदद मिली।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ विश्लेषक - कमोडिटी रिसर्च, मानव मोदी
वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी के भाव
वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स पर सोना वायदा 0.76 प्रतिशत बढ़कर 2,728.10 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। एशियाई बाजार घंटों में चांदी वायदा 1.70 प्रतिशत चढ़कर 32.32 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

चैन से कटेगा बुढ़ापा, रिटायरमेंट के लिए इस फॉर्मूले से तैयार कीजिए फंड



हर कोई रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहता है। लेकिन इसके लिए सही से तैयारी नहीं करते। आपको तीस साल की उम्र से रिटायरमेंट प्लान करना शुरू करना देना चाहिए। इसके लिए आपको खास तरीके से बचत और निवेश भी करना चाहिए। इससे आप लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान सकते हैं।

नई दिल्ली। महंगाई और वित्तीय अनिश्चितता दिन-ब-दिन बढ़ जा रही है। उम्र के साथ ही जोखिम और भी ज्यादा बढ़

जाते हैं। बुजुर्ग अवस्था में सेहत से जुड़ी परेशानियां भी रोज की बात हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं की है, तो आपको काफी मुश्किल हो सकती है।

हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिसके आधार पर आप अपने रिटायरमेंट को काफी बेहतर बना सकते हैं। फिर आपको बुढ़ापे में किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

कितने समय में होना है रिटायर
रिटायरमेंट प्लानिंग के वक्त आपका गोल एकदम निश्चित होना चाहिए। आप अपना रिटायरमेंट खुद निश्चित कर सकते हैं

या फिर रिटायरमेंट के बचे हुए साल के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। आपके रिटायरमेंट में जितना कम समय होगा, आपको उतनी ही अधिक बचत करनी होगी, ताकि जल्द से जल्द रिटायरमेंट के लिए जरूरी फंड तैयार हो पाए। साथ ही, गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम भी कसनी होगी।

कैसे तैयार करें रिटायरमेंट फंड
रिटायरमेंट के प्लान पर अमल से पहले आपको अपने सभी खर्चों का हिसाब लगाना होगा। अगर कोई कर्ज है, तो उसे भी जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। फिर जरूरी खर्चों के बाद बचत का प्लान करें। आपको एकमुश्त पैसे नहीं बचाने हैं। आप छोटी-

छोटी सेविंग के माध्यम से भी रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए वित्तीय तौर पर अनुशासित होकर लगातार निवेश करते रहना होगा।

किस स्कीम में करें निवेश
रिटायरमेंट के लिए आप अलग-अलग स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन, आपको रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना होगा। इसका मतलब कि अपनी सारी बचत किसी एक स्कीम में न लगाएं। आप कुछ शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। कुछ एसआईपी या डेट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप किसी

फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं।

ये योजनाएं हो सकती हैं बेस्ट
आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) से लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकते हैं। आप अपनी सहूलियत से फंड हाउस और स्कीम चुन सकते हैं। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार की स्कीम है। इसमें निवेश भी अच्छा विकल्प है। इस स्कीम में पैसा 60 साल में मैच्योर होता है। आप अटल पेंशन योजना की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन, आपको कमाई इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। इसमें निवेश की

मर्जर के बाद बदल जाएगा विस्तार का फ्लाइट कोड, एयर इंडिया ने दी पूरी जानकारी

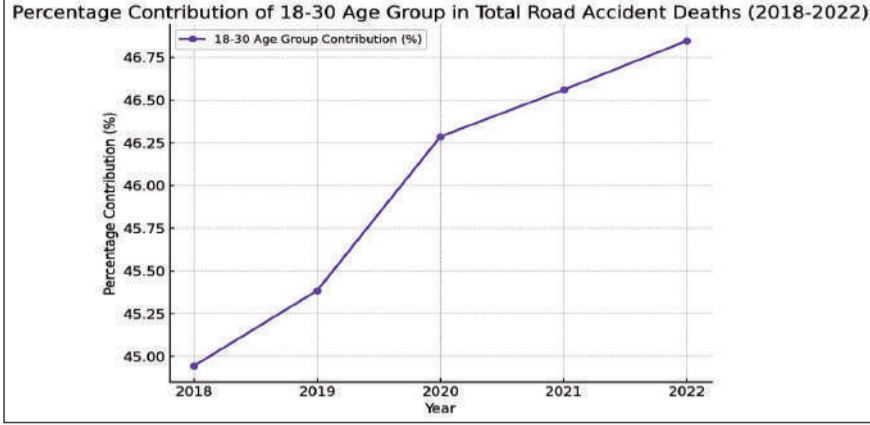
Air India-Vistara Merger टटा ग्रुप (Tata Group) के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया (Air India) और सिंगापुर एयरलाइन्स विस्तारा (Vistara) का मर्जर होने वाला है। इस मर्जर के बाद क्या सभी चीजों में बदलाव होगा या नहीं। ऐसे कई सवाल आ रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब एयर इंडिया ने दे दिया है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि मर्जर के बाद क्या बदलाव होगा और क्या नहीं।

नई दिल्ली। एयरलाइन सेक्टर का सबसे बड़ा मर्जर होने वाला है। टटा ग्रुप (Tata Group) के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया (Air India) और सिंगापुर एयरलाइन्स विस्तारा (Vistara) का जल्द ही मर्जर हो जाएगा। इस मर्जर के बाद भी यात्रियों को सभी सुविधाएं सुचारु रूप से मिलेंगी, यानी पैसेंजर्स को मिलने वाली सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद फ्लिंग चीजों में बदलाव होगा। इसकी जानकारी एयर इंडिया ने दी। एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके पैसेंजर्स को सभी जानकारी दी।

मर्जर के बाद बदल जाएगा फ्लाइट कोड : एयर इंडिया के एक्स पोस्ट के अनुसार मर्जर के बाद विस्तारा के फ्लाइट कोड में बदलाव होगा। अब विस्तारा के फ्लाइट कोड की शुरुआत एयर इंडिया कोड (Air India Flight Code) के स्पेशल 4 डिजिट से होगी। इस 4 डिजिट की शुरुआती डिजिट '2' होगा। एयर इंडिया ने उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान में विस्तारा का कोड 'यूके 955' है तो वह मर्जर के एआई 2955 बन जाएगा। कोड के बदल जाने के बाद पैकेज आसानी से बुकिंग करते समय फ्लाइट की पहचान कर पाएंगे।

इसके अलावा एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि मर्जर के बाद क्लब विस्तारा (Club Vistara) के मेंबर्स को एयर इंडिया के 'फ्लाइंग रिटर्न्स' (Flying Returns) प्रोग्राम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं, विस्तारा के 'फ्लाइंग रिटर्न्स' भी नए अवतार 'महाराजा क्लब' में बदल जाएगा।
नहीं बदलेगी टाईमिंग : कई पैसेंजर्स को लगता था कि मर्जर के बाद फ्लाइट की टाईमिंग में भी बदलाव होगा। फ्लाइट को टाईमिंग को लेकर एयर इंडिया ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन रूट और टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा फ्लाइट एक्सपीरियंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

“सड़क हादसों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है”



मोहित सोनी कुक्षी

सड़क दुर्घटनाएं आज एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, खासकर युवाओं के बीच। बढ़ती युवा आबादी और उनकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग न होने से सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बाइक और कार के तेज गति से चलाने की होड़, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, शराब और नशे में गाड़ी चलाना, सिग्नल तोड़ना, तेज हॉर्न लगाना, और आपस में रस लगाना जैसी गतिविधियां दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रही हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण

1. **तेज गति:** युवा अक्सर तेज गति से गाड़ी चलाने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि तेज गति में गाड़ी चलाने पर प्रतिक्रिया देने का समय कम हो जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

2. **नशे में ड्राइविंग:** शराब या अन्य नशे का सेवन करके गाड़ी चलाने से न सिर्फ चालक की सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि यह दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक होता है।

3. **सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी:** बिना हेलमेट के बाइक चलाना या सीट बेल्ट का उपयोग न करना दुर्घटनाओं के समय गंभीर चोट या मौत का कारण बनता है। यह देखा गया है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है।

4. **सिग्नल तोड़ना और रेंसिंग:** चौराहों पर सिग्नल का पालन न करना न सिर्फ गैर-कानूनी है, बल्कि यह बहुत ही खतरनाक है। साथ ही, सड़क पर दोस्तों के साथ रस लगाना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह जानलेवा साबित हो सकता है।

5. **अन्य चालकों को परेशान करना:** तेज

हॉर्न का इस्तेमाल या लापरवाही से कट मारने से अन्य चालकों का ध्यान भंग होता है, जिससे वे अचानक से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है।

सड़क हादसों का तुलनात्मक अध्ययन (वर्षवार)

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल हजारों युवा अपनी जान गंवाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा है।

जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं, हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले युवाओं की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। यह समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है।

समाधान के सुझाव

1. **सड़क सुरक्षा शिक्षा:** युवाओं को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए।

2. **कानूनों का सख्त पालन:** तेज गति से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने और सिग्नल तोड़ने पर भारी जुर्माना और सजा होनी चाहिए। पुलिस को सड़क पर सख्त निगरानी करना चाहिए।

3. **सुरक्षा उपकरणों का उपयोग:** हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए ताकि वे दुर्घटना के समय प्रभावी रहें।

4. **स्वयं की जिम्मेदारी:** युवा खुद भी यह समझें कि उनकी एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। उन्हें समझदारी और

जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलानी चाहिए।

5. **परिवार और समाज की भूमिका:** माता-पिता और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही, उन्हें नशे से दूर रखने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक बनाने में मदद करें।

निष्कर्ष

सड़क दुर्घटनाओं में हो रही युवाओं की मौतें एक गंभीर समस्या है, जिसे केवल कानून से नहीं, बल्कि सामूहिक जागरूकता और जिम्मेदारी से हल किया जा सकता है। हर व्यक्ति की जान कीमती है, और छोटी-छोटी सावधानियां दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती हैं। युवा ऊर्जा और साहस का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं, जिससे न केवल उनकी सुरक्षा होगी, बल्कि समाज भी सुरक्षित रहेगा।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद; SC ने कहा- लड़कियां बालिग, मर्जी से आश्रम में रह रहीं

आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्यवाही को बंद कर दिया है। दो बहनों के बयान के बाद शीर्ष अदालत ने केस को बंद करने का निर्णय लिया। बता दें कि एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर अपनी दो बेटियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से दो लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। एक व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन परिसर में उसकी दो बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं। दोनों ने कहा है कि वे स्वेच्छा और बिना किसी दबाव के आश्रम में रह रही हैं।

पिता ने लगाया ब्रेनवॉश करने का आरोप

इससे पहले सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास उच्च न्यायालय में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी दो बेटियों को ब्रेनवॉश करके आश्रम में रखा गया है। बड़ी बेटी गीता की उम्र 42 और छोटी बेटी लता की उम्र 39 साल है। इसके बाद 30 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश तमिलनाडु पुलिस को दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश पर लग चुकीं रोक

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 150 तमिलनाडु पुलिस के जवान जांच करने ईशा फाउंडेशन पहुंचे। ईशा फाउंडेशन ने आरोपों पर कहा कि दोनों लड़कियां अपनी स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईशा फाउंडेशन ने देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

बैंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, जब्त की गई करोड़ों की कोकेन समेत कई नशीली दवाएं

बैंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट ने शहर के फॉरेन पोस्ट ऑफिस में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 21.17 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की। इकाई ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए प्रतिबंधित पदार्थों वाले 606 पार्सल की खोज की जब्त की गई दवाओं में हाइड्रो गांजा एलएसडी एमडीएमए क्रिस्टल एक्ट्रेस टी टैबलेट हेरोइन कोकीन एम्फैटमिन चरस और गांजा तेल शामिल थे।

नई दिल्ली। बैंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट ने शहर के फॉरेन पोस्ट ऑफिस में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 21.17 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की। इकाई ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए प्रतिबंधित पदार्थों वाले 606 पार्सल की खोज की।

अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, थाईलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों से तस्करी कर लाई गई दवाओं को कुत्ते दस्ते की मदद से 3,500 से अधिक संदिग्ध पार्सलों का निरीक्षण करने के बाद पकड़ा गया। डाक सेवा के माध्यम से पदार्थ को कर रहा था।



आयात

जब्त की गई दवाओं में हाइड्रो गांजा, एलएसडी, एमडीएमए क्रिस्टल, एक्ट्रेस टी टैबलेट, हेरोइन, कोकीन, एम्फैटमिन, चरस और गांजा तेल शामिल थे। जांच से यह भी पता चला कि आरोपी बैंगलुरु में बड़ी हुई कीमतों पर बेचने के लिए भारतीय डाक सेवा के माध्यम से इन पदार्थों का आयात कर रहा था। यह तस्करी कथित तौर पर शहर में जमाने-माने ग्राहकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध धन कमाने के अभियान का हिस्सा थी।

सीसीबी नारकोटिक्स यूनिट ने पहले इस साल 12 मामले दर्ज किए थे और इसी तरह की मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों में शामिल कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

सितंबर में, एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज दो मामलों और सीसीबी स्टेशन में एक मामले के सिलसिले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ये मामले, डाकघर छापे के साथ, बैंगलुरु में नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा हैं।

मामले की जांच जारी

संयुक्त अभियान क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए सीसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट की तरफ से चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है। जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि अधिकारी प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के आयात और वितरण में शामिल व्यक्तियों के नेटवर्क का पता लगाना जारी रखेंगे।

ओबीसी को तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, सात साल में जो नहीं हुआ, क्या वो अब होगा ?

मोदी सरकार ओबीसी के क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ा सकती है। दायरे को बढ़ाने के लिए मांग भी की जा रही थी जिस पर जल्द फैसला हो सकता है। क्रीमी लेयर के दायरे को आठ लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया जा सकता है। बता दें कि आखिरी बढ़ोतरी 2017 में हुई थी। महाराष्ट्र सरकार भी इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेज चुकी है।

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर दायरे को बढ़ाने की मांग पर जल्द फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने ओबीसी संगठनों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसके तहत क्रीमी लेयर की सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख है, जो 2017 से नहीं बढ़ाई गई है। पहले हर तीन साल में इसकी समीक्षा होती थी।

महाराष्ट्र सरकार ने दिया केंद्र को प्रस्ताव

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने भी ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इस प्रस्ताव से पहले ही केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अंधकार मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ओबीसी संगठनों से चर्चा की है। ओबीसी संगठनों ने की 15 लाख तक बढ़ाने की मांग

ओबीसी संगठनों ने क्रीमी लेयर के दायरे को 15 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई और लोगों की आय बढ़ी है, उसको देखते हुए बढ़ोतरी 15 लाख से कम ठीक नहीं होगी।

संसदीय समिति की बैठक में भी उठा मुद्दा

क्रीमी लेयर का यह मुद्दा पिछले महीने हुई संसदीय समिति की बैठक में भी उठा। समिति ने इसमें ओबीसी देरी पर मंत्रालय के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया था। मौजूदा समय में ओबीसी के क्रीमी लेयर के निर्धारण में वेतन और कुषि आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल कारोबार से होने वाली आय को जोड़ा जाता है। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वालों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है।

क्या है क्रीमी लेयर (Creamy Layer)?

क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वंचित लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए ही क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है।

अभी आठ लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम वाले परिवार को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा, गुपुए, बी सेवा में काम करने वाले अधिकारियों के बच्चे भी इसमें आते हैं। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों के बच्चे भी इसके हिस्से में आते हैं।

विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2022 में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मौजूदा समय में अब्बास अंसारी यूपी के कासगंज जेल में बंद हैं। इससे पहले धमका कर बैनामा कराने के मामले में अब्बास को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

नौ मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था।

2022 में ईडी ने दर्ज किया था केस

मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 4

नवंबर 2022 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था। मौजूदा समय में अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। ईडी के आरोप के मुताबिक अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया था।

ईडी ने जारी किया था लुकआउट नोटिस

इससे पहले अब्बास अंसारी को पिस्टल सटारक जमीन बैनामा कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसके अलावा 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

ईडी मुख्तार और अब्बास अंसारी के लखनऊ, दिल्ली और गाजीपुर स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की इसी साल 28 मार्च को मौत हो गई थी। हालांकि परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया था।

रंगदारी मांगने का भी आरोप

इसी साल सितंबर महीने में पुलिस ने अब्बास अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह मामला चित्रकूट जिले की कर्वाी कोतवाली में दर्ज किया गया है। अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में रहते समय रंगदारी मांगने का आरोप है।

सीरवी समाज इलेक्ट्रॉनिक सीटी वडेर की प्रथम वर्ष गांट हर्षोल्लास के साथ मनाई

जयकारों के बीच चढ़ाई ध्वजा आईमाताजी के जयकारों से गुंजायमान हुआ इलेक्ट्रॉनिक सीटी



परिवहन विशेष न्यूज

बैंगलुरु: सीरवी समाज ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वडेर की प्रथम वर्ष गांट हर्षोल्लास के साथ मनाई। गुरुवार को मंदिर में ब्रह्मों मुहुर्त में हवन अनुष्ठान किया गया। हवन के मुख्य यजमान मांगीलाल काग व उनके परिवार ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुति दी। उसके बाद ध्वाजा के लाभार्थी देवाराम, मूलाराम सोलंकी परिवार द्वारा जयकारों के बीच ध्वजा चढ़ाई गई। अखंड ज्योत के लाभार्थी रतनलाल बर्फा परिवार द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई। पश्चात माताजी की महा आरती हुई। उसके बाद आमसभा का शुभारंभ हुआ आम

सभा में पिछले वर्ष की बोलियां के दानदाताओं का स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष नाथूराम परिहार ने स्वागत किया। इससे पूर्व संस्था जागरण का आयोजन किया गया। भजनों का आगाज आईमाता तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर महादेव भजन मंडली ने राजस्थानी लोक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजनों के कार्यक्रम में चढ़ावों की 4 बोलियां बोलनी गईं। जिसमें समाज बंधुओं ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। समोरह के मुख्य अतिथि सीरवी कर्नाटक महासभा के महासचिव अमरचन्द्र सातपुरा ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर आनेकल वडेर से बालूयाम,

चन्द्रापुर वडेर के अध्यक्ष हरजीराम काग, अतिबेले वडेर के पूर्व अध्यक्ष मूलाराम काग, होसारावे वडेर के अध्यक्ष तुलसाराम लखावत, जिगनी वडेर के अध्यक्ष वडेर के अध्यक्ष मांगीलाल राठौड़ का ट्रस्ट की ओर से माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल मोगरेचा, संस्था के सचिव रामलाल हाम्मड, उपाध्यक्ष कानाराम हाम्मड, कोषाध्यक्ष मांगीलाल काग, सह कोषाध्यक्ष तुलसाराम सेणचा, सूचना मंत्री देवाराम सोलंकी, एवं समाज के अनेक गणमान्य बंधुगण उपस्थित रहे।

बीजेडी के कई नेता कांग्रेस के सम्पर्क में हैं

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: बीजेडी के कई नेता कांग्रेस के सम्पर्क में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बारबाटी के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम ने इस तरह का बयान देने के लिए बीजेडी की आलोचना की है। मोकिम ने आज कहा कि बीजेडी के कई नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस से संपर्क किया है। दिवाली तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इसके बाद बीजे से कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से पराजित नेता शामिल हैं।

मोकिम के बयान से बीजेडी खेमे में हड़कंप मच गया है। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कौन सा नेता भाजपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। हालांकि, मोकिम ने जो कहा वह था कि अध्यक्ष पद संभालने के बाद पराजित नेताओं में से कई बीजेडी छोड़ देंगे और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। मोकिम ने कहा कि वहां बीजेपी के भी कुछ नेता हैं।

ऐसा लगता है कि मोकिम के बयान को लेकर राजनीतिक टिप्पणीकारों ने जो भविष्यवाणी की थी, वह सच होने जा रही है। नवगंतुक अब बीजे में जो चल रहा है उससे नाखुश है। पार्टी में नेता को लेकर घमासान मचा हुआ है। सार्वजनिक रूप से नवीन पटनायक पार्टी के अध्यक्ष हैं जबकि निजी तौर पर वी कार्तिकेयन पांडेयन पार्टी के नेता हैं। वह टीम के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। अपने संदेश में पार्टी नेता असंतुष्टों पर जमकर निशाना साध रहे हैं।

